राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण सोमवार 02 फरवरी 2026 वर्ष-9,अंक-10 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

लोकसभा में 9वां बजट पेश

ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट 15 प्रतिशत बढ़ा : इनकम टैक्स में बदलाव नहीं, 17 कैंसर मेडिसिन ड्यूटी फ्री, 3 आयुर्वेदिक एम्स

एजेंसी

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वे 85 मिनट बोलीं, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और 3 नए आयुर्वेदिक AIIMS जैसी नई बातें कही हैं। बजट भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान भी नहीं हुआ। सीतारमण लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंचीं जरूर, लेकिन इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली घोषणाएं नहीं कीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में वित्त मंत्री ने जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। डिफेंस बजट की खास बात यह है कि हथियार खरीदी और सेना के आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले इस बार 2.19 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह पूंजीगत खर्च में सीधे 22% की बढ़ोतरी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं, ताकि आम लोग उसे आसानी से भर सकें। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। ये एडवांस कैंसर की इंपोर्ट होने वाली दवाएं हैं। अभी 5% कस्टम ड्यूटी लगती थी। हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं।ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में सीतारमण ने जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। डिफेंस बजट की खास बात यह है कि इसमें हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल 2.19 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

पीएम मोदी बोले: ये युवा शक्ति का बजट

पीएम मोदी ने आम बजट को युवाओं को बजट बताया है। कहा कि देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी है। ये स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करने का प्रयास है। सबसे बड़ी पूंजी नागरिक,

राहुल ने कहा: युवाओं को कुछ नहीं मिला

उधर विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया। राहुल गांधी ने कहा, युवाओं के लिए रोजगार वाला बजट नहीं है। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर गिर रहा है। निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं। घरेलू बचत में भारी गिरावट आ रही है।

पीएम मोदी ने संत निरंजन दास के पैर छुए

जालंधर के डेरा बल्लां में बोले: मेरा रिश्ता संत रविदास की जन्मभूमि काशी से

एजेंसी

जालंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदासिया समाज के जालंधर स्थित सबसे बड़े धार्मिक स्थल डेरा सचखंड बल्लां पहुंच गए हैं। यहां वह डेरे के संत निरंजन दास जी से 10 मिनट बंद कमरे में मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह पंगत में बैठकर लंगर छकेंगे। पीएम मोदी ने संत निरंजन दास के पैर छूकर श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा- मेरा रिश्ता संत रविदास जी की जन्मभूमि काशी से है। मैं पंजाब दी धरती नूं नमन करदा हां (मैं पंजाब की धरती को नमन करता हूं)। वहीं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डेरे के प्रबंधक ने कहा कि हम ढट के आने से बहुत खुश हैं। पहली बार कोई प्रधानमंत्री हमारे बीच आया। पीएम दिल्ली से आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने पहले आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरू रविदास महाराज जी एयरपोर्ट, आदमपुर रखने का उद्घाटन किया। इसके बाद लुधियाना के हलवारा स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा- मध्य प्रदेश के सागर में श्री गुरु रविदास का मंदिर बन रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि उसका नींव पत्थर रखने का मौका भी मुझे मिला था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको श्री गुरु रविदास जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। जो बोले, सो निर्भय। बहुत-बहुत धन्यवाद। पीएम ने कहा- एक समय था जब भारत के प्रोडक्ट दुनिया में सबसे अच्छे होते थे। गुलामी के कालखंड में इसे खराब कर दिया गया। अब हमें क्वालिटी पर ध्यान देकर फिर से दुनिया में नंबर वन प्रोडक्ट बनाने वाला बनना है। पीएम मोदी बोले- गुरु रविदास ने भी श्रम का सम्मान किया है। हमारी सरकार भी गुरु रविदास के विचारों को निरंतर आगे बढ़ा रही है। जैसे अब संत रविदास जयंती का राष्ट्रीय आयोजन होने लगा है। कई राज्यों ने इस दिन पर छुट्टी घोषित की है। पीएम मोदी ने कहा- मैं पंजाब के युवाओं, फैक्ट्री मालिकों से एक अपील करना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए दुनिया का बाजार तो खोल दिया है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना होगा कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। दुनिया कहे कि यह प्रोड्क्ट भारत से आए हैं। लोग कहें कि यह सामान भारत में बना है तो वेल्यू फॉर मनी है। हमें क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने होंगे। आज कंपीटिशन बहुत है। अगर हमने प्रोडक्ट क्वालिटी वाले नहीं बनाए तो यह मौका हमारे हाथ से चला जाएगा। पीएम ने कहा- आपको तो पता ही है कि जालंधर स्पोर्ट्स के तौर पर जाना जाता है।

कोलकाता के रेस्टोरेंट में मटन की जगह बीफ परोसा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक रेस्टोरेंट में मटन की जगह बीफ परोसने का मामला सामने आया है। बंगाली यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर सायक चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि उन्होंने मटन स्टेक ऑर्डर किया था, लेकिन उन्हें बीफ स्टेक परोस दिया या। उन्होंने बीफ को मटन समझकर खा लिया। सायक चक्रवर्ती शुक्रवार रात अपने दोस्तों के साथ पार्क स्ट्रीट स्थित एक पब-रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे। उन्होंने एक मटन स्टेक ऑर्डर किया था। कुछ देर बाद वेटर एक और प्लेट लेकर आया और कहा कि यह मटन स्टेक है। तब सायक को शक हुआ कि पहले परोसा गया स्टेक मटन नहीं था। सायक ने जब वेटर से सवाल किया तो उसने दावा किया कि दो स्टेक ऑर्डर किए गए थे। एक मटन और एक बीफ। हालांकि सायक का कहना है कि उन्होंने सिर्फ एक मटन स्टेक ऑर्डर किया था। सायक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडियो पर पोस्ट किया। वीडियो में सायक वेटर से बहस करते और जवाब मांगते दिख रहे हैं। रेस्टोरेंट मैनेजर और वेटर वीडियो में माफी मांगते नजर आते हैं। वीडियो में सायक यह कहते भी सुने गए कि वह ब्राह्मण हैं। इस घटना से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसके बाद पार्क स्ट्रीट पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के

असम सीएम बोले: कांग्रेस को सिर्फ अवैध बांग्लादेशियों की चिंता

हजार राहुल गांधी-गौरव गोगोई मेरी कुछ नहीं कर सकते

एजेंसी

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस को सिर्फ अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की चिंता है, न कि असम के मूल निवासियों के हितों की। उन्होंने गुवाहाटी में पत्रकारों से कहा कि हजार गौरव गोगोई और राहुल गांधी भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी असम के लोगों के लिए स्थिति बहुत नाजुक है, और यह राज्य में उनके अस्तित्व का सवाल है। मिया मुसलमान विवाद पर उन्होंने कहा कि मिया मुसलमानों शब्द मैंने नहीं गढ़ा है और यह शब्द खुद वो समुदाय इस्तेमाल करता है जो बांग्लादेश से आकर बस गए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस शब्द को इस्तेमाल किया है। X पर किए पोस्ट में सरमा ने लिखा कि ये अदालत के अपने शब्द हैं। असम पर चुपचाप और धोखे से हो रहा जनसांख्यिकीय हमला निचले असम के भू-रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिलों के नुकसान का कारण बन सकता है। अवैध प्रवासियों की संख्या इन जिलों को मुस्लिम-बहुल क्षेत्र में बदल रही है। इसके बाद यह सिर्फ समय की बात होगी जब बांग्लादेश के साथ उनके विलय की मांग की जा सकती है। निचले असम के नुकसान से उत्तर पूर्व का पूरा भूभाग बाकी भारत से अलग हो जाएगा, और उस क्षेत्र के समृद्ध प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र के हाथ से निकल जाएंगे। सरमा ने यह भी कहा कि ऐसी चिंताओं को स्वीकार करना सांप्रदायिकता या नफरत नहीं है। सीएम के बयान पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सीएम सरमा अपने बयानों को सही ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एक कार्यकारी रिपोर्ट की भाषा को सुप्रीम कोर्ट से जोड़ना अदालत की अवमानना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 27 जनवरी को कहा था कि राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में 4 से 5 लाख मिया मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि हिमंत बिस्व सरमा और भाजपा सीधे तौर पर मिया समुदाय के खिलाफ हैं। उन्होंने लोगों से मिया समुदाय को परेशान करने की अपील की। उनका कहना था कि जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी, वे असम नहीं छोड़ेंगे। मिया बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अपमानजनक शब्द है। असम सीएम के मुताबिक वे मूल निवासियों के संसाधनों, नौकरियों और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तिनसुकिया जिले के डिगबोई में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से सरमा ने कहा वोट चोरी का मतलब यह है कि हम कुछ मिया वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं। आदर्श रूप से उन्हें असम में वोट डालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, बल्कि बांग्लादेश में वोट देना चाहिए। सीएम ने कहा, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे असम में वोट न कर सकें। हिमंत बिस्व सरमा ने आगे कहा था कि जो कोई भी किसी भी तरह से मिया को परेशानी दे सकता है, वह दे। आप भी इसमें शामिल हैं। रिक्शा में अगर किराया 5 रुपये है, तो उन्हें 4 रुपये दीजिए। जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी, वे असम नहीं छोड़ेंगे। 27 दिसंबर को SIR ड्राफ्ट रोल में असम में फिलहाल 2.51 करोड़ मतदाता हैं।

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन

एजेंसी

नई दिल्ली। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। शनिवार देर रात हुई बारिश और हल्की हवाओं ने राजधानी और आसपास के इलाकों में ठंडक को और बढ़ा दिया है, जिससे लोगों को ठिठुरन का एहसास हो रहा है। रविवार सुबह भी रुक रुककर बारिश देखी गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूवार्नुमानों के अनुसार, यह मौसमी हलचल अभी जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार, 1 से 7 फरवरी के बीच दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में तीन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इन विक्षोभों का प्रभाव न केवल मैदानी इलाकों में बारिश के रूप में दिखेगा, बल्कि हिमालयी राज्यों में बर्फबारी की भी उम्मीद है। पहले दो पश्चिमी विक्षोभ 31 जनवरी से 3 फरवरी तक अपना असर दिखाएंगे, जबकि तीसरा विक्षोभ 5 फरवरी से सक्रिय होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

मणिपुर में उग्रवादी रंगदारी मांग रहे, डर से बाजार बंद

एजेंसी

इंफाल। मणिपुर में उग्रवादी संगठन हर सेक्टर के कारोबारियों को फोन कर रंगदारी मांग रहे हैं। व्यापारी कहते हैं कि शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास हमारा लेखा-जोखा हैं। उनके डर बाजार बंद होने लगे हैं। इसके विरोध में शनिवार को इंफाल में हजारों लोगों ने 5 किमी लंबी रैली निकाली। यह रैली सेव मणिपुर अभियान के तहत कोकोमी नामक संगठन ने आयोजित की थी। कर्ज में डूबे मारवाड़ी, पंजाबी कारोबारी भी राज्य छोड़ रहे हैं। इस बाजार से जुड़े मारवाड़ी समुदाय के 500 परिवार में से 40-50 परिवार, पंजाबी समुदाय के 100 परिवार में से 20-25 परिवार बिजनेस ठप होने से पलायन कर चुके हैं। राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थांगल और पाउना बाजार में 60-65% ही व्यापार हो रहा है। मणिपुर एफएमसीजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय पाटनी कहते है, चुराचांदपुर, कांग्पोक्पी और चंदेल जिलों तथा आसपास के इलाकों में 30-37% कारोबार होता था, जो अब बंद है।

यूपी: 'पत्थर की मूर्ति बन गई पत्नी'

पति ने मचाया ऐसा शोर, दौड़े-दौड़े पहुंचे अधिकारी; महिला की हो रही तलाश

एजेंसी

मैनपुरी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी कुरावली के गिहार कॉलोनी के पीछे मोहल्ला फर्दखाना में शनिवार को एक घर में महिला के पत्थर की मूर्ति बनने की अफवाह फैल गई। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार और थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने लोगों को समझाया कि यह केवल अफवाह और अंधविश्वास है।यह अफवाह थाना क्षेत्र के गांव हीरापुर निवासी संजू सिंह के उस दावे से फैली कि घर में सो रही उसकी पत्नी शनिवार सुबह पत्थर की मूर्ति बन गई है। संजू ने कहा कि उसकी पत्नी बीमार रहती है और घर में रखी प्रतिमा की पूजा करती है। अब वह खुद मूर्ति बन गई है। बाहर जमा भीड़ को शांत कर स्थिति को नियंत्रित किया। नायब तहसीलदार अखिल गोयल ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक भ्रम फैलाने का मामला है। पुलिस ने कहा कि संजू को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि वह आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि उसकी पत्नी कहां गई।

जांच में पता चला कि संबंधित व्यक्ति की पत्नी के पत्थर बनने की बात सिर्फ अफवाह है। व्यक्ति की पत्नी की तलाश की जा रही है।

-सच्चिदानंद सिंह, क्षेत्राधिकारी, कुरावली

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बांग्लादेश चुनाव के साये में खून, खौफ और अस्थिरता लोकतंत्र की परीक्षा या इतिहास की पुनरावृत्ति

इस पूरे संकट की पृष्ठभूमि में बांग्लादेश की राजनीति का हालिया इतिहास बेहद अहम है। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी, जिसने देश में निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा किया। हसीना की पार्टी अवामी लीग को मई 2025 में बैन कर दिया गया, जिससे राजनीतिक संतुलन पूरी तरह बदल गया।

(लेखक – कांतिलाल मांडोत)

बांग्लादेश एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ चुनाव लोकतंत्र का उत्सव बनने के बजाय डर, हिंसा और असुरक्षा की तस्वीर पेश कर रहे हैं। 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले देश में जिस तरह राजनीतिक हिंसा तेज़ हुई है, उसने न सिर्फ आम नागरिकों को भयभीत किया है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंता बढ़ा दी है। बीते 48 दिनों में 16 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या और सिर्फ 24 घंटे में 82 लोगों के घायल होने की घटनाएँ यह बताने के लिए काफी हैं कि हालात कितने नाजुक हो चुके हैं। राजधानी ढाका से लेकर मयमनसिंह, लालमोनिरहाट और चुआडांगा तक हिंसा की आग फैल चुकी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया खून से सनी दिख रही है।

चुनाव की घोषणा 11 दिसंबर को हुई थी और उसी दिन से तनाव का सिलसिला शुरू हो गया। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार अब तक देशभर में 62 से अधिक चुनावी झड़पें दर्ज की जा चुकी हैं। इन घटनाओं में सबसे ज्यादा निशाना विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यकर्ता बने हैं। मारे गए 16 लोगों में से 13 बीएनपी से जुड़े बताए जा रहे हैं। यह आँकड़े केवल संख्या नहीं हैं, बल्कि उस दहशत का प्रतीक हैं जो चुनाव से पहले राजनीतिक मैदान में फैलाई जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि यह हिंसा सुनियोजित है और इसका मकसद चुनाव को प्रभावित करना तथा मतदाताओं को डराना है।

हिंसा की प्रकृति और तरीके भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 16 में से 7 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या गोली मारकर की गई। इससे साफ संकेत मिलता है कि अवैध हथियारों की खुलेआम मौजूदगी है। जुलाई 2024 के आंदोलन के दौरान लूटे गए हजारों हथियारों में से अब तक बड़ी संख्या में हथियार और गोलियाँ बरामद नहीं हो सकी हैं। यही हथियार आज चुनावी हिंसा को और खतरनाक बना रहे हैं। आम लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जब सरकार हथियारों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही, तो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कैसे संभव होंगे।

हालिया झड़पों की बात करें तो मयमनसिंह में बीएनपी समर्थकों और बागी उम्मीदवारों के बीच हुई हिंसा में करीब 20 लोग घायल हुए। लालमोनिरहाट में बीएनपी और जमात समर्थकों के बीच टकराव में कम से कम 11 लोग घायल हुए। चुआडांगा के आलमडांगा क्षेत्र में भी ऐसी ही झड़पें हुईं, जहाँ नौ से अधिक लोग घायल हो गए। सबसे चिंताजनक बात यह है कि हिंसा अब सिर्फ दूरदराज़ इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजधानी ढाका तक पहुँच चुकी है। ढाका में एनसीपी उम्मीदवार अरिफुल इस्लाम अदीब पर हुए हमले ने यह साबित कर दिया कि कोई भी सुरक्षित नहीं है।

इस राजनीतिक हिंसा का सामाजिक असर बेहद गहरा है। चुनाव का समय आमतौर पर बहस, प्रचार और लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा का होता है, लेकिन बांग्लादेश में यह दौर डर और अस्थिरता का बन गया है। लोग घरों से निकलने में हिचक रहे हैं, व्यापार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है। सबसे ज़्यादा नुकसान अल्पसंख्यक समुदायों को झेलना पड़ा है। पहले हिंदू समुदाय और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाए जाने की घटनाएँ सामने आई थीं, जिनमें कई निर्दोष लोगों की जान गई और उनके घर जलाए गए। अब राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर चुनावी माहौल को और ज़हरीला किया जा रहा है। इससे साफ है कि हिंसा का दायरा लगातार फैल रहा है और कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है।

इस पूरे संकट की पृष्ठभूमि में बांग्लादेश की राजनीति का हालिया इतिहास बेहद अहम है। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी, जिसने देश में निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा किया। हसीना की पार्टी अवामी लीग को मई 2025 में बैन कर दिया गया, जिससे राजनीतिक संतुलन पूरी तरह बदल गया। यह चुनाव हसीना के 15 साल लंबे शासन के बाद पहली बार ऐसे हालात में हो रहा है जब सत्ता में उनकी पार्टी नहीं है और इसे निष्पक्ष चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन मौजूदा हिंसा ने इस उम्मीद पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

राजनीतिक समीकरण भी काफी जटिल हैं। बीएनपी इस समय 10 दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, जबकि जमात 11 दलों के अलग गठबंधन के साथ मैदान में है। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश और जतीया पार्टी जैसे दल भी चुनाव लड़ रहे हैं। इतने सारे गुटों की मौजूदगी में टकराव की आशंका पहले से ही थी, लेकिन जिस स्तर पर हिंसा हो रही है, उसने सभी को चौंका दिया है। विपक्ष सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहने का आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।

विशेषज्ञों को बांग्लादेश के चुनावी इतिहास को देखते हुए डर है कि कहीं एक बार फिर खून-खराबे की पुरानी कहानी न दोहराई जाए। 1991 के चुनाव में 49 लोगों की मौत हुई थी, 2008 में 21 और 2014 में 142 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 2018 और 2023 के चुनाव भी विवादों और हिंसा से अछूते नहीं रहे थे, जिन्हें विपक्ष ने एकतरफा बताया था। ऐसे में मौजूदा हालात देखकर यह आशंका और गहरी हो जाती है कि क्या बांग्लादेश इस बार सचमुच शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा। कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन या तो दबाव में हैं या निष्क्रिय। कई मामलों में पुलिस ने राजनीतिक हत्याओं के पीछे किसी साजिश से इनकार किया है, लेकिन जमीन पर फैले डर को नकारा नहीं जा सकता। जब राजनीतिक कार्यकर्ता खुलेआम मारे जा रहे हों और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई न हो, तो आम जनता का भरोसा कानून पर से उठना स्वाभाविक है। यही भरोसे की कमी हिंसा को और बढ़ावा देती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश की छवि दांव पर है। एक ओर अंतरिम सरकार यह संदेश देना चाहती है कि देश लोकतांत्रिक रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर बहता खून इस दावे को कमजोर कर रहा है। पड़ोसी देश भारत में रह रहीं शेख हसीना को लेकर भी तनाव बना हुआ है। उन्हें वापस भेजने की मांग की जा रही है और कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद यह मुद्दा और संवेदनशील हो गया है। इन सबके बावजूद हिंसा का थमना यह बताता है कि समस्या सिर्फ किसी एक व्यक्ति या पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट का रूप ले चुकी है।

आज बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह चुनाव को हिंसा से अलग कैसे रखे। लोकतंत्र की असली परीक्षा सिर्फ मतदान कराने से नहीं होती, बल्कि यह सुनिश्चित करने से होती है कि हर नागरिक बिना डर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। अगर चुनाव खौफ के साये में होते हैं, तो उनके नतीजे चाहे जो हों, वे जनता का विश्वास नहीं जीत पाएंगे। अंतरिम सरकार, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज को मिलकर यह समझना होगा कि हिंसा किसी के हित में नहीं है।

अगर हालात पर तुरंत काबू नहीं पाया गया, तो यह हिंसा केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लंबे समय तक देश की स्थिरता और सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुँचा सकती है। बांग्लादेश पहले ही आर्थिक चुनौतियों, बेरोज़गारी और सामाजिक तनाव से जूझ रहा है। ऐसे में राजनीतिक हिंसा आग में घी डालने का काम कर रही है। अब वक्त है कि सभी पक्ष जिम्मेदारी दिखाएँ, हथियारों पर नियंत्रण हो, दोषियों को सजा मिले और चुनाव को सचमुच लोकतंत्र का पर्व बनाया जाए।

बांग्लादेश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में हिंसा पर कितनी सख्ती से लगाम लगाई जाती है। यह चुनाव सिर्फ सत्ता का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह तय करेगा कि देश डर के रास्ते पर चलेगा या लोकतांत्रिक स्थिरता की ओर बढ़ेगा। इतिहास की पुनरावृत्ति होगी या एक नया अध्याय लिखा जाएगा, इसका जवाब आने वाले हफ्तों में सामने होगा। (वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार,स्तम्भकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

प्रदूषण बनाम टैरिफ

दावोस में हाल ही में संपन्न वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा के दौरान यह बात शिद्दत से उठी कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ के मुकाबले प्रदूषण ज्यादा घातक असर दिखा रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और आईएमएफ की पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने इकोनॉमिक फोरम में चर्चा के दौरान कहा कि व्यापार बढ़ाने की कवायद में अकसर व्यापारिक बाधाओं और नियमों की बात की जाती है, लेकिन आर्थिक तरक्की में बाधक प्रदूषण जैसे घटकों की चर्चा कम ही होती है। चर्चा में भारत में प्रदूषण की भयावहता का जिक्र करते हुए कहा गया कि भारत पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुकाबले प्रदूषण का असर ज्यादा घातक व दूरगामी है। फोरम में साल 2022 में विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला दिया गया कि भारत में हर साल सत्रह लाख लोगों की मौत प्रदूषण से हो जाती है। ये आंकड़ा भारत में मरने वालों का अट्ठारह फीसदी बैठता है। जो कहीं न कहीं आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने के साथ ही बहुमूल्य जीवन भी लीलता है। कमोबेश यह घातकता जीडीपी पर भी असर डालती है। निस्संदेह, प्रदूषण से होने वाली मौतों से केवल एक परिवार ही नहीं, पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है। देश की श्रम शक्ति का ह्रास होता है और आर्थिकी पर दूरगामी प्रभाव होते हैं। वहीं आर्थिकी पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि प्रदूषण के चलते निवेशकों के भरोसे पर भी दुष्प्रभाव होता है। इससे निवेशकों का आकर्षण कम होता है। निस्संदेह, निवेशक के मन में भय होता है कि यदि वह इसी प्रदूषित वातावरण में रहता है तो यह उसके लिये यह घातक हो सकता है। इसमें दो राय नहीं कि प्रदूषण की भयावह स्थिति दुनिया में किसी भी देश की छवि को नुकसान जरूर पहुंचाती है। जिससे निवेशक बेहतर विकल्प की तलाश में अन्य देशों का रुख कर सकते हैं। ऐसे में प्रदूषण के संकट को युद्धस्तर पर निपटाने की जरूरत महसूस की जा रही है। निस्संदेह, भारत में प्रदूषण का संकट एक यथार्थ है। यह भी हकीकत है कि देश के नीति-नियंता प्रदूषण संकट के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आते। जब-जब प्रदूषण संकट गहराता है तो आग लगने पर कुआं खोदने की कवायद की जाती है। कोर्ट की फटकार व नियामक एजेंसियों की सख्ती के बाद शासन-प्रशासन हरकत में आता है। लेकिन गीता गोपीनाथ के तर्कों के कुछ अर्धसत्य भी हैं। इसमें दो राय नहीं कि अमेरिका के इशारे पर काम करने वाली वैश्विक एजेंसियां विकासशील देशों को लेकर अपनी सुविधा के हिसाब से प्रतीक-प्रतिमान गढ़ती रही हैं। आईएमएफ जैसी संस्थाओं को अमेरिकी कूटनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यहां तक कि इन संस्थाओं में उच्च पदों पर बैठे भारतीय अधिकारी भी अमेरिका के सुरों में गाते नजर आते हैं। सवाल गोपीनाथ के बयान के समय का भी है जब अमेरिका न केवल भारत पर अन्यायपूर्ण टैरिफ लगा रहा है बल्कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते को भी अपनी शर्तों के अनुरूप अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहा है। बहरहाल, इसके बावजूद यह एक हकीकत है कि हमारे देश में प्रदूषण संकट बड़ा है, जिसे देश के नीति-नियंता गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिसके चलते करोड़ों भारतीयों को अपनी जमा-पूंजी अपने व परिवार के उपचार में खर्च करनी पड़ती है। निस्संदेह, प्रदूषण के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कानूनों को सरल बनाने की भी जरूरत है ताकि उन पर अमल आसानी से हो सके। इसके अलावा लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है कि देश की आबोहवा सुधारने के लिये उन्हें भी कुछ त्याग करने होंगे। उन्हें अपनी विलसिता की जीवन शैली में बदलाव लाकर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारना होगा। निश्चित रूप से प्रदूषण को आर्थिक चुनौती के रूप में भी देखने की जरूरत है। खासकर जब भारत खुद को वैश्विक आर्थिक और विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिये प्रयासरत है। हमारा मकसद हो कि हमारे शहर स्वच्छ रहें और नागरिकों के लिये जीवन परिस्थितियां स्वास्थ्य के अनुकूल हों।

विकसित भारत की उड़ान : बजट 2026 के आर्थिक संकल्प

(लेखक-ललित गर्ग)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत नवीन केंद्रीय बजट को यदि समग्र दृष्टि से देखा जाए तो यह केवल एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के स्वप्न की ठोस आधारशिला के रूप में सामने आता है। यह बजट उस रिफॉर्म एक्सप्रेस की तरह है जो बीते वर्षों में चली आर्थिक सुधारों की पटरियों पर तेज़ गति से दौड़ते हुए अब भारत को उच्च विकास, समावेशन और आत्मनिर्भरता की नई ऊँचाइयों की ओर ले जाने का दावा करता है। तुलनात्मक, विवेचनात्मक और समीक्षात्मक दृष्टि से यह बजट पूर्ववर्ती बजटों की निरंतरता को बनाए रखते हुए कई नए आयाम भी जोड़ता है, जो इसे ऐतिहासिक और भविष्यगामी बनाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों के बजटों की तुलना में यह बजट अधिक आत्मविश्वास के साथ सामने आता है। महामारी, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के बीच भारत ने जिस आर्थिक मजबूती का प्रदर्शन किया है, उसका आत्मविश्वास इस बजट में स्पष्ट झलकता है। जहां पूर्व बजटों में संकट प्रबंधन और अर्थव्यवस्था को संभालने पर अधिक जोर था, वहीं यह बजट विकास की ऊंची उड़ान के लिए रनवे तैयार करता दिखता है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का मंत्र यहां नारे से आगे बढ़कर नीतिगत संरचना का रूप लेता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट की दृष्टि विशेष रूप से विवेचनात्मक है। चिकित्सा अवसंरचना के विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और डिजिटल हेल्थ के माध्यम से गांव-गांव तक चिकित्सा सुविधाएं पहुँचाने की दिशा में किए गए प्रावधान यह संकेत देते हैं कि सरकार स्वास्थ्य को केवल खर्च नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश मान रही है। यदि पिछले दशक के बजटों से तुलना की जाए तो स्वास्थ्य पर आवंटन और दृष्टिकोण दोनों में गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। यह बदलाव भारत को न केवल स्वस्थ समाज की ओर ले जाने वाला है, बल्कि उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि को भी दीर्घकाल में मजबूती देगा।

शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट की आत्मा दूरदर्शी है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़ी शिक्षा पर बल यह दर्शाता है कि सरकार भविष्य के भारत के लिए आज के युवाओं को तैयार करना चाहती है। पूर्ववर्ती बजटों में शिक्षा पर खर्च की चर्चा होती थी, लेकिन इस बजट में शिक्षा को रोजगार और नवाचार से जोड़ने की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है। यह एक ऐसा बिंदु है जहाँ यह बजट तुलनात्मक रूप से अधिक परिपक्व और व्यावहारिक प्रतीत होता है।

विकास की दृष्टि से यह बजट 'इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लस समावेशन' का मॉडल प्रस्तुत करता है। रेलवे कॉरिडोरों के विकास, लॉजिस्टिक्स को सशक्त बनाने, सड़क, बंदरगाह और शहरी अवसंरचना में निवेश को जिस तरह प्राथमिकता दी गई है, वह भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का मजबूत हिस्सा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सात रेलवे कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा केवल परिवहन सुविधा का विस्तार नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलन का माध्यम भी है। यदि इसे पिछले बजटों से जोड़कर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि सरकार अब बुनियादी ढांचे को विकास का इंजन मानकर लगातार गति दे रही है।

ग्रामीण भारत के संदर्भ में यह बजट विशेष उल्लेख के योग्य है। कृषि, ग्रामीण अवसंरचना, सिंचाई, किसान कल्याण और ग्रामीण उद्यमिता से जुड़े प्रावधान यह संकेत देते हैं कि गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की मंशा केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है। मेडिकल सुविधाओं, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार से ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता सुधरने की संभावना बढ़ती है। यह आत्मनिर्भर भारत की उस परिकल्पना को साकार करता है जिसमें गांव मजबूत होंगे तो देश स्वतः मजबूत होगा।

नारी शक्ति के सशक्तिकरण के संदर्भ में भी बजट का दृष्टिकोण तुलनात्मक रूप से व्यापक है। महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमिता, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े विशेष प्रावधान यह दर्शाते हैं कि महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। गरीबों और वंचित वर्गों के लिए लक्षित योजनाएं इस बजट को सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी संतुलित बनाती हैं। समीक्षात्मक रूप से देखा जाए तो यह बजट कल्याण और विकास के बीच संतुलन साधने का प्रयास करता है, जो किसी भी दीर्घकालिक आर्थिक नीति की अनिवार्य शर्त है।

युवाओं के लिए यह बजट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप, नवाचार, स्किल इंडिया, रोजगार सृजन और नई तकनीकों में निवेश युवाओं की आकांक्षाओं को संबोधित करता है। यदि इसे आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो यह भी स्पष्ट होता है कि बजट में क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक यथार्थ का भी ध्यान रखा गया है। हालांकि आलोचक इसे चुनावी बजट कह सकते हैं, लेकिन विवेचनात्मक दृष्टि से यह कहना अधिक उचित होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बजट का जन-आकांक्षाओं से जुड़ा होना स्वाभाविक है, बशर्ते वह दीर्घकालिक विकास को बाधित न करे। इस बजट में दीर्घकालिक दृष्टि और तात्कालिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन दिखाई देता है।

समीक्षात्मक रूप से यह स्वीकार करना होगा कि किसी भी बजट की सफलता केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से तय होती है। संसाधनों की उपलब्धता, राज्यों के साथ समन्वय और पारदर्शी प्रशासन इस बजट की वास्तविक परीक्षा होंगे। फिर भी, तुलनात्मक दृष्टि से यह बजट भारत की आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव प्रतीत होता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट भारत के विकास की ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। यह वर्तमान की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भविष्य की संभावनाओं के लिए रास्ता तैयार करता है।

स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना, ग्रामीण विकास, नारी शक्ति और युवाओं को केंद्र में रखकर यह बजट 'विकसित भारत 2047' की दिशा में एक सशक्त कदम है। यदि इसे निरंतर सुधार, जवाबदेही और समावेशी क्रियान्वयन का साथ मिला, तो यह बजट इतिहास में केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव के रूप में याद किया जाएगा।

चिंतन मनन

सन्मार्ग की प्रवृत्ति

उत्तम कार्य की कार्य प्रणाली भी प्रायः उत्तम होती है। दूसरों की सेवा या सहायता करनी है, तो प्रायः मधुर भाषण, नम्रता, दान, उपहार आदि द्वारा उसे संतुष्ट किया जाता है। परन्तु कई बार इसके विपरीत क्रिया-प्रणाली ऐसी कठोर, तीक्ष्ण एवं कटु बनानी पड़ती है कि लोगों को भ्रम हो जाता है कि कहीं यह दुर्भाव से प्रेरित होकर तो नहीं किया गया। ऐसे अवसरों पर वास्तविकता का निर्णय करने में बहुत सावधानी बरतने पड़ती है। सीधे-सादे अवसरों पर सीधी-सादी प्रणाली से भली प्रकार काम चल जाता है। भूखे, प्यासे की सहायता करनी है, तो वह कार्य अन्न-जल देने के सीधे-सादे तरीके से चल जाता है। किसी दुःखी या अभावग्रस्त को अभीष्ट वस्तुएं देकर उसकी सेवा की जा सकती है। धर्मशाला, कुआं, पाठशाला, अनाथालय, औषधालय आदि द्वारा लोकसेवा की जा सकती है। ऐसे कार्य निश्चय ही श्रेष्ठ हैं और उनकी आवश्यकता व उपयोगिता सर्वत्र स्वीकारी जा सकती है। परन्तु कई बार ऐसी सेवा की भी बड़ी आवश्यकता होती है, जो प्रत्यक्ष में बुराई मालूम पड़ती है और उसे करने वाले को अपयश ओढ़ना पड़ता है। इस मार्ग को अपनाने का साहस हर किसी में नहीं होता। दुष्ट और अज्ञानियों को उस मार्ग से छुड़ाना, जिस पर वे बड़ी ममता और अहंकार के साथ प्रवृत्त हो रहे हैं, साधारण काम नहीं है। सीधे आदमी की भूल ज्ञान से, तर्क से, समझाने से सुधर जाती है पर जिनकी मनोभूमि अज्ञानान्धकार से कलुषित हो, साथ ही जिनके पास कुछ शक्ति भी है, वे ऐसे मदान्ध हो जाते हैं कि सीधी-सादी क्रिया-प्रणाली का उन पर प्रायः कुछ असर नहीं होता। मनुष्य शरीर धारण करने पर भी जिनमें पशुत्व की प्रधानता है, दुनिया में उनकी कमी नहीं है। उन्हें ज्ञान, तर्क, नम्रता, सज्जनता, सहनशीलता से अनीति के दुःखदाई मार्ग से पीछे नहीं हटाया जा सकता। पशु केवल दो चीजें पहचानता है- एक लोभ, दूसरा भय। दाना, घास खिला उसे ललचा कर कहीं भी ले जाइए, वह पीछे-पीछे चलेगा या लाठी का डर दिखा जिधर चाहे उधर ले जा सकते हैं। भय या लोभ से अज्ञानियों को, कुमार्गगामियों को सन्मार्ग में प्रवृत्त किया जा सकता है। भय उत्पन्न करने के लिए दंड का आश्रय लिया जाता है। लोभ के लिए कोई ऐसा आकषर्ण उसके सामने उपस्थित करना पड़ता है जो आज की अपेक्षा अधिक सुखदायी हो। नशेबाजी, व्यभिचार आदि के दुष्परिणाम को बढ़ा-चढ़ाकर, बताकर कई बार उस ओर चलने वालों को इतना डरा दिया जाता है कि वे उसे स्वतः छोड़ देते हैं।

विचार मंथन

बजट के बाद बाजार में हाहाकार

(लेखक- सनत जैन)

- सोना चांदी और शेयर बाजार अर्श से फर्श पर

1 फरवरी 2026 को रविवार के दिन भारत का पहली बार बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। बजट में मुख्य लक्ष्य आर्थिक वृद्धि, निवेश को बढ़ावा, टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास को बहाल करने की कोशिश की गई है। सरकार ने पूंजीगत व्यय को बढ़ाया है। घरेलू उत्पादन और इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश बढ़े, रोजगार सृजन के अवसर को बढ़ावा मिले, बजट में इसका प्रयास किया गया है। इसका क्या परिणाम होगा यह कहना मुश्किल है। बजट प्रस्तुत होने के तुरंत बाद शेयर बाजार में हाहाकार देखने को मिला। स्टॉक मार्केट पर बिकवाली और सेंसेक्स में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी प्रमुख सूचकांक नीचे आए। कुछ कंपनियों और निवेशकों पर उच्च डेरिवेटिव टैक्स और व्यापार पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का असर शेयर बाजार में देखने को मिला है। केंद्रीय बजट में कुछ वस्तुएं महंगी हुईं, जैसे खनिज और स्क्रैप जैसे कच्चे माल पर टैक्स एवं शुल्क को बढ़ाया गया है। शराब और वायदा कारोबार पर टैक्स को बढ़ाया गया है। कुछ आवश्यक दवाइयाँ इस बजट में सस्ती करने का प्रावधान किया गया है। कैंसर और शुगर जैसी बीमारियों के उपयोग में आने वाली दवाइयों की कीमतें कम होंगी, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। विदेशी संपत्ति की घोषणा पर छूट और अघोषित संपत्ति पर राहत, आपराधिक मामलों और जुर्माने में छूट दी गई है। यह सरकारी खजाने को राहत देने वाला एक बड़ा कदम हो सकता है। विदेशी आय और विदेशों में जो संपत्ति भारतीयों ने अवैध रूप से एकत्रित कर रखी है, इसकी घोषणा करने पर सरकार को भारी टैक्स मिलने की आशा है। विदेश मे संपत्ति की घोषणा करने के बाद आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे। भारत सरकार ने विदेशी संपत्ति की घोषणा करने के लिए यह नया अवसर दिया है। मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के पूर्व घोषणा की थी कि वह विदेश में जमा काला धन भारत लेकर आएंगे उस दिशा में इसे एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।

आयकर दाताओं के लिए एक 6 महीने की विशिष्ट घोषणा योजना है। घोषणा करने वाले व्यक्ति की विदेशी आय/संपत्ति का मूल्य यदि 1 करोड़ तक है, वह इसे घोषित करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे 30 प्रतिशत टैक्स प्लस 30 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स (कुल 60प्रतिशत) चुकाकर इसे भारत में घोषित कर सकता है। भारत सरकार ने ऐसे मामलों में अभियोजन से छूट देने की घोषणा की है। दूसरी श्रेणी में वे नागरिक आएंगे जिन्होंने आयकर विवरणी में आय तो घोषित की थी, लेकिन संपत्ति की घोषणा नहीं की थी। उनके लिए यह सीमा 5 करोड़ रखी गई है। 1 लाख एक मुस्त देकर दंड व अभियोजन से मुक्ति देने की घोषणा की गई है। अघोषित गैर-अचल विदेशी संपत्तियों के लिए सीमित राशि देकर अपराधिक मामले और अभियोजन से छूट का प्रावधान किया गया है। जो पहले नहीं था। केंद्र सरकार के इस प्रावधान से विदेशी निवेशकों और दीर्घकालिक भारतीय निवेशको के बीच भरोसा बहाल करने की कोशिश के रूप में बजट के इस प्रावधान को देखा जा रहा है। बजट में कुछ मामलों में टैक्स छूट से राहत दी गई है। टैक्स छूट में विदेश यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा के लिए रेमिटेंस पर अब टीसीएस केवल 2प्रतिशत किया गया है, जिससे उन भारतीय परिवारों के लिए छूट के रूप में देखा जा रहा है, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ाई करने या जो परिवार विदेश घूमने के लिए जाते हैं उनको राहत मिलेगी। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट से जो परेशानी हो रही थी उसमें उन्हें राहत मिलना तय है।

कई वस्तुओं पर भी टीसीएस और टीडीएस नियमों में सुधार कर करदाताओं को राहत देने का प्रयास किया गया है। इस बजट में जो वस्तुएं और सेवाएं महंगी हुई हैं, उनमें वायदा और डेरिवेटिव बाजार पर ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया है, जिससे ट्रेडिंग में खर्च बढ़ना तय है। इसका खराब असर शेयर बाजार और वायदा कारोबार में देखने को मिलेगा। बजट में सरकार ने खनिज, शराब जैसे उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया गया है जिससे यह सेवाएं और वस्तुएं महंगी होगी। 2026-27 के बजट में सरकार ने आर्थिक स्थिरता, टैक्स सिस्टम में सुधार कर नियमों को आसान बनाने की कोशिश की है लेकिन जो परिवर्तन किए हैं वह बहुत मामूली हैं, इसका कोई असर देखने को मिलेगा कहना मुश्किल है। बजट में जहाँ कुछ सेवाएं और वस्तुएँ महंगी हुई हैं, वहीं कुछ सेवाएं और वस्तुएं सस्ती भी हुई हैं। जैसे विदेशी यात्रा खर्च, आवश्यक दवाईयाँ, विदेशी आय-संपत्ति की घोषणा पर आपराधिक कार्यवाही की छूट तथा दंड के प्रावधान में छूट दी गई है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

शेयर बाजार भारी गिरावट पर बंद, सेंसेक्स 1546 अंक टूटा

निफ्टी 495 अंक नीचे आया, निवेशकों के 9.55 लाख करोड़ डूबे

मुम्बई । भारतीय शेयर बाजार बजट के कारण रविवार को खुला रहा पर इस विशेष कारोबारी सत्र में भारी गिरावट रही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट 2026 भाषण शुरु होते ही बाजार गिरने लगा और अंत तक यही स्थिति रही। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स अंत में 1546.84 अंक की गिरावट के साथ ही 80,722.94 अंक पर बंद हुआ। वहीं पचास शेयरों वाला एनएसई (निफ्टी) अंत में 495.20 अंक टूटकर गिरकर 24,825.45 पर बंद हुआ। बाजार जानकारों के अनसार बजट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) को बढ़ाने की घोषणा से बाजार में गिरावट आई है क्योंकि इससे विदेशी निवेशकों में बिकवाली की आशंका बढ़ गयी। इससे बेंचमार्क इंडेक्स 2 फीसदी से ज्यादा गिर गए। इसके साथ ही मेटल स्टॉक्स में भारी बिकवाली से भी बाजार पर दबाव आया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कमोडिटी फ्यूचर्स पर एसटीटी को 0.02 फीसदी से बढ़ाकर 0.05 फीसदी करने की घोषणा की है। प्रस्ताव के तहत ऑप्शंस प्रीमियम पर एसटीटी को 0.1 फीसदी से बढ़ाकर 0.15 फीसदी कर दिया गया है।

आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स की कंपनियों में एसबीआई का शेयर सबसे ज्यादा गिरा। इसमें 5.61 फीसदी की गिरावट रही। वहीं अदाणी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीसी, टाटा स्टील, अल्ट्रा सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएंडटी, बजाज फाइनेंस, मारुति, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी और बजाज फिनसर्व के शेयर नीचे आये। वहीं दूसरी ओर टीसीएस लगभग 2 फीसदी उछलकर बंद हुआ। इसके अलावा इंफोसिस, सन फार्मा और टाइटन के शेयरों में भी तेजी रही।

वहीं निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 2.24 फीसदी नीचे आया जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 2.73 फीसदी गिरा। आज आईटी को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स में बिकवाली हावी रही। निफ्टी पीएसयू बैंक 5.57 फीसदी नीचे आया। इसके बाद निफ्टी मेटल 4.05 फीसदी, ऑटो 2.09 फीसदी, बैंक 2 फीसदी, फाइनेंशियल सर्विसेज 2.31 फीसदी, एफएमसीजी 2.29 फीसदी, रियल्टी 2.22 फीसदी नीचे आये।

वित्त मंत्री ने कहा कि हम विकसित भारत के विजन की तरफ काम करते रहेंगे। हम ग्लोबल मार्केट के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं।

वहीं वैश्विक स्तर पर शुक्रवार को अमेरिकी बाजार गिरावट पर बंद हुए थे। इसका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के फेडरल रिजर्व के पूर्व गवर्नर केविन वार्श को फेड चेयर जेरोम पॉवेल के उत्तराधिकारी के रूप में नामित करना रहा।

एसएंडपी 500 में 0.43 फीसदी की गिरावट आई जबकि डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 0.36 फीसदी नीचे रहा।

वहीं एशियाई बाजार भी शुक्रवार को ज्यादातर नुकसान के साथ बंद हुए थे। ।

चीन का शंघाई कंपोजिट 0.96 फीसदी गिरा, ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.65 फीसदी और जापान का निक्केई 225 में 0.09 फीसदी की मामूली गिरावट रही पर दक्षिा कोरिया का कोस्पी 0.06 फीसदी टूटकर बंद हुआ।

वहीं इससे पहले आज केंद्रीय बजट को लेकर आयोजित विशेष कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की तेजी के साथ हुई।

बाजार में जोरदार गिरावट से निवेशकों को 16 लाख करोड़ का नुकसान

- बाजार का मार्केट कैप बजट वाले दिन घटकर 4,44,34,637.85 करोड़ रुपए रह गया

मुंबई । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार नौवीं बार बजट पेश किए जाने के बाद भारतीय शेयर बाजार में रविवार, 1 फरवरी को इंट्राडे कारोबार के दौरान जोरदार गिरावट देखने को मिली। अचानक मार्केट क्रैश के कारण निवेशकों के 16 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बजट में राजकोषीय अनुशासन के साथ आर्थिक विकास पर जोर दिया गया लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में बढ़ोतरी के प्रस्ताव से बाजार की धारणा कमजोर पड़ गई। बजट के दिन विशेष कारोबारी सत्र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स एक समय 2,400 अंक तक टूट गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 79,899.42 अंक के दिन के निचले स्तर तक फिसल गया। सुबह सेंसेक्स 82,388.97 अंक पर खुला था और शुरुआती कारोबार में 82,726.65 अंक के उच्च स्तर तक पहुंचा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी भारी दबाव देखने को मिला। निफ्टी 50 इंडेक्स में कारोबार के दौरान करीब 749 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह 24,571.75 अंक के निचले स्तर तक आ गया। बाजार में आई इस तेज गिरावट का मुख्य कारण फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कारोबार पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रहा। बजट में फ्यूचर्स पर एसटीटी को 0.02 फीसदी से बढ़ाकर 0.05 फीसदी करने और ऑप्शंस ट्रांजैक्शन पर एसटीटी को 0.01 फीसदी से बढ़ाकर 0.15 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस घोषणा के बाद एफएंडओ से जुड़े शेयरों में तेज बिकवाली देखी गई। बाजार में आई गिरावट का सीधा असर निवेशकों की संपत्ति पर पड़ा। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, 30 जनवरी को बाजार का कुल मार्केट कैप 4,60,02,240.35 करोड़ रुपए था, जो बजट वाले दिन घटकर 4,44,34,637.85 करोड़ रुपए रह गया।

वित्तमंत्री सीतारमण ने MSME के लिए 10,000 करोड़ रु मुहैया कराने साथ 4 उपायों का रखा प्रस्ताव

नई दिल्ली ।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने हमेशा निर्णायक रूप से अस्पष्टता की जगह काम को, बातों की जगह सुधार को और लोक-लुभावन नीतियों की जगह लोगों को प्राथमिकता दी है। संसद में आज बजट 2026-27 में कहा कि सरकार तीन कर्तव्यों से प्रेरित है। इनमें से पहला कर्तव्य- आर्थिक विकास को गति देते हुए इसे निरंतर कायम रखना है तथा उत्पादकता व प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हुए अस्थिर वैश्विक स्थिति के इस दौर में मजबूती कायम रखना है।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को विकास का मत्वपूर्ण इंजन करार देते हुए वित्त मंत्री ने इसके विकास के लिए तीन सूत्रीय दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा। इनमें पहला इक्विटि समर्थन है जिसमें उन्होंने लघु तथा मध्यम उद्यम के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक समर्पित निधि का प्रस्ताव रखा है। इसके अंतर्गत चुनिंदा मानकों पर भविष्य में उत्कृष्ट उद्यमों का सृजन करना है। वित्त मंत्री ने वर्ष 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत कोष में बढ़ोतरी के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों को मदद पहुंचाना और जोखिम पूंजी तक उनकी पहुंच बनाए रखना है। व्यवसायगत सहायता पर बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि खासकर टियर-2 और टियर-3 नगरों में 'कॉर्पोरेट मित्रों' के समूह का विकास के लिए के लिए अल्पावधि की मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों और व्यवहारिक टूल्स की डिजाइन के लिए सरकार आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई जैसे संस्थानों की मदद करेगी। ये यह प्रणाणित अर्ध-पेशेवर एमएसएमई को कम लागत पर अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की व्यवस्था की है। इसकी क्षमता का पूरा फायदा उठाने के लिए उन्होंने 4 उपायों का प्रस्ताव रखा है-

(i) एमएसएमई से सावर्जनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा समस्त खरीदों के लिए ट्रेड्स को लेन-देन निपटान प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करने का अधिदेश करना,

(ii) ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर बीजक छूट के लिए सीजीटीएमएसई के जरिये ऋण गारंटी सहायता तंत्र की शुरुआत करना,

(iii) एमएसएमई से सरकारी खरीदों के बारे में फाइनेंसर्स तक जानकारी साझा करने के लिए जीईएम को टीआरईडीएस को जोड़ना,

(iv) ट्रेड्स प्राप्तियों को आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में प्रस्तुत करना। इसका उद्देश्य नगदी एवं लेनदेनों के निपटान करते हुए एक दूसरा बाजार विकसित करना है।

एक्सपोर्ट में क्रेटा-स्कार्पियो पीछे छोडा टोयोटा हायराइडर को

नई दिल्ली । एक्सपोर्ट के मामले में टोयोटा हाइराइडर ने सभी मॉडलों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में भारतीय बाजार के बाहर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली एसयूवी की सूची सामने आई है। बीते महीने दिसंबर 2025 में टोयोटा हायराइडर की 5,164 यूनिटें विदेश भेजी गईं, जो इसे इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली एसयूवी बनाता है। खास बात यह है कि देश में लगातार टॉप पर रहने वाली नेक्सन, क्रेटा और स्कॉर्पियो जैसी एसयूवी भी एक्सपोर्ट में इसके सामने टिक नहीं पाईं। दूसरे स्थान पर मारुति सुजुकी जिम्नी रही जिसकी 4,592 यूनिटें एक्सपोर्ट हुईं। वहीं ई-विटारा की 2,724 और फ्रोंक्स की 2,390 यूनिटें विदेशों में भेजी गईं। हालांकि फ्रोंक्स ने पिछली बार की तुलना में काफी गिरावट दर्ज की। महिंद्रा की एक्सयूवी 3एक्सह ने 999 यूनिट एक्सपोर्ट कर अपनी मौजूदगी मजबूत की। किया सोनेट की 966 और ग्रैंड विटारा की 849 यूनिटें एक्सपोर्ट हुईं। रेनॉ काइगर ने भी इस बार अच्छा प्रदर्शन करते हुए 751 यूनिटें एक्सपोर्ट कीं, जो पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। क्रेटा की 511 और अल्कजार की 450 यूनिटें एक्सपोर्ट हुईं। मारुति ब्रेजा की केवल 53 और स्कॉर्पियो की 50 यूनिटें ही विदेशी बाजार में भेजी गईं, जबकि उनके घरेलू बाजार में यह आंकड़ा बहुत बड़ा रहता है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि टोयोटा हायराइडर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रही है।

जनवरी 2026 में जीएसटी संग्रह 1.93 लाख करोड़, मजबूत बढ़ोतरी जारी

- जीएसटी कलेक्शन में 6.2 फीसदी की वार्षिक बढ़ोतरी

नई दिल्ली । जनवरी 2026 में भारत का कुल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) संग्रह 1.93 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 6.2 फीसदी अधिक है। यह दिसंबर 2025 के 1.75 लाख करोड़ रुपये से भी ऊपर है। शुद्ध जीएसटी राजस्व करीब 1.71 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें 7.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। कुल जीएसटी रिफंड में 3.1 फीसदी की गिरावट हुई और यह 22,665 करोड़ रुपये पर रहा। विशेषज्ञों के अनुसार, रिफंड में कमी के बावजूद कर संग्रह में स्थिरता आर्थिक गतिविधियों और मजबूत टैक्स कलेक्शन को दर्शाती है। जनवरी में तंबाकू उत्पादों से उपकर 5,768 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले वर्ष जनवरी के 13,009 करोड़ रुपये की तुलना में काफी कम है, क्योंकि सरकार ने सितंबर 2025 से विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर उपकर घटा दिया और केवल तंबाकू तथा संबंधित उत्पादों पर क्षतिपूर्ति उपकर लागू किया। घरेलू लेनदेन से जीएसटी संग्रह 4.8 फीसदी बढ़कर 1.41 लाख करोड़ रुपये हुआ, जबकि आयात से राजस्व 10.1 फीसदी बढ़कर 52,253 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के बावजूद टैक्स कलेक्शन मजबूत बना हुआ है। दिसंबर 2025 में कुल जीएसटी संग्रह 1.74 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें नेट जीएसटी 1.45 लाख करोड़ रुपये था। घरेलू जीएसटी 1.22 लाख करोड़ और आयात जीएसटी 51,977 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। इस अवधि में रिफंड 28,980 करोड़ रुपये तक पहुंचा। विश्लेषक मानते हैं कि जीएसटी दरों में कटौती के बावजूद संग्रह में तेजी से आर्थिक मजबूती और कर प्रशासन की दक्षता दर्शाती है।

हुंदै मोटर इंडिया की जनवरी में बिक्री 11.5 फीसदी बढ़ी

नई दिल्ली । हुंदै मोटर इंडिया ने जनवरी 2025 में कुल 73,137 इकाई की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल जनवरी में 65,603 इकाई थी। कंपनी के अनुसार यह कुल बिक्री में 11.5 प्रतिशत की मजबूत सालाना वृद्धि दर्शाती है। घरेलू थोक बिक्री जनवरी 2025 में 59,107 इकाई रही, जो पिछले साल इसी अवधि में 54,003 इकाई थी। यह हुंदै के घरेलू बाजार में अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री है। निर्यात बिक्री भी मजबूत रही। जनवरी 2025 में 14,030 इकाई निर्यात की गईं, जबकि जनवरी 2024 में यह संख्या 11,600 इकाई थी, यानी लगभग 21 फीसदी वृद्धि। हुंदै मोटर इंडिया के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने कहा कि ये आंकड़े सिर्फ ब्रांड नेतृत्व नहीं बल्कि कर्मचारियों, भागीदारों और ग्राहकों की सामूहिक सफलता को भी दर्शाते हैं। कुल मिलाकर हुंदै मोटर इंडिया ने जनवरी में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में मजबूत प्रदर्शन किया, जिसमें घरेलू बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई।

ईरान और अमेरिका के बीच जंग हुई तो खतरे में पड़ जाएगी दुनिया की अर्थव्यवस्था

तेहरान।

मिडिल ईस्ट इस समय एक बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती तल्खी ने युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है। दोनों देशों के बीच जुबानी जंग अब सैन्य शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो चुकी है। ईरान ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मूज पर उसकी पकड़ मजबूत है और वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। दूसरी ओर, अमेरिका ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में किसी भी असुरक्षित या उकसावे वाली कार्रवाई को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बढ़ते टकराव के बीच अरब देशों, अरब लीग और कई वैश्विक शक्तियों ने चिंता जताई है कि यदि हालात बिगड़े, तो इसका खामियाजा सिर्फ मिडिल ईस्ट को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा।

वजह ये है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। ईरान और अमेरिका के रिश्तों में यह कड़वाहट नई नहीं है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां पहले के मुकाबले अधिक विस्फोटक नजर आ रही हैं। ईरान के भीतर बढ़ता आर्थिक संकट, बेरोजगारी और मुद्रा के गिरते मूल्य ने वहां की आंतरिक स्थिति को अस्थिर कर दिया है, जिससे उपजे सरकार विरोधी प्रदर्शनों और उन पर हुई सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने मानवाधिकारों का मुद्दा गरमा दिया है। अमेरिका ने इन घटनाओं के आधार पर ईरान पर नए कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। वहीं, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल से शुरू हुआ ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विवाद एक बार फिर केंद्र में है। अमेरिका का रुख सख्त है कि यदि ईरान वार्ता की मेज पर नहीं आता, तो उसके खिलाफ सैन्य विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। तनाव का मुख्य केंद्र इस समय स्ट्रेट ऑफ होर्मूज बना हुआ है, जिसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ माना जाता है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा और भारी मात्रा में गैस इसी संकरे रास्ते से गुजरती है। सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े तेल निर्यातक इसी रूट पर निर्भर हैं। वर्तमान में ईरान की नौसेना यहां अपना वार्षिक युद्धाभ्यास कर रही है, जो दुनिया को उसकी सैन्य शक्ति दिखाने का एक तरीका है।

तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी के दाम 49 रुपए बढ़ाए

- दिल्ली में 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1,740.50 रुपए पहुंची

नई दिल्ली । तेल कंपनियों ने रविवार को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 49 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर 1,740.50 रुपये में मिलेगा। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलो) के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और कैटरिंग कारोबार से जुड़े लोगों पर सीधा असर पड़ा है। गैस महंगी होने से खाना बनाने की लागत बढ़ गई है, जिससे कारोबारियों की परेशानियां फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी तेल कंपनियां कमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ा चुकी हैं। पिछली बार 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम में 111 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे दिल्ली में इसकी कीमत 1,580.50 रुपये से बढ़कर 1,691.50 रुपये हो गई थी। हालांकि बीते कुछ महीनों में कमर्शियल गैस के दाम अपेक्षाकृत नरम रहे थे। अप्रैल 2025 से अब तक छह बार कीमतों में कटौती की गई थी और कुल मिलाकर 223 रुपये तक की राहत मिली थी। लेकिन अब लगातार बढ़ोतरी से एक बार फिर कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है।

रॉयल एनफील्ड की दिसंबर की बिक्री में आया उछाल

नई दिल्ली ।

रॉयल एनफील्ड कंपनी फिलहाल भारतीय बाजार में 350सीसी से 650सीसी सेगमेंट तक कुल नौ मॉडल बेचती है और खास बात यह है कि लगभग सभी अपने-अपने सेगमेंट में अग्रणी बने हुए हैं। रॉयल एनफील्ड ने दिसंबर 2025 में एक बार फिर अपने सबसे लोकप्रिय मॉडल क्लासिक 350 की बदौलत मजबूत सेल्स दर्ज कीं।

इन सबमें क्लासिक 350 कंपनी के लिए 'सोने का अंडा देने वाली मुर्गी' साबित हो रही है। दिसंबर में इसकी सबसे ज्यादा 34,958 यूनिटें बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 5,321 यूनिट अधिक हैं। इस मॉडल ने सालाना आधार पर 17.95फीसदी की शानदार ग्रोथ दर्ज की और 37.52फीसदी मार्केट शेयर हासिल किया। बुलेट 350 भी बिक्री में तेजी से आगे बढ़ी। दिसंबर 2025 में इसकी 24,849 यूनिटें बिकीं, जो दिसंबर 2024 की तुलना में 76.87फीसदी की ग्रोथ है। वहीं हंटर 350 ने 20,654 यूनिटों की बिक्री के साथ 50.28फीसदी की तेजी दर्ज की। मीटिओर 350 की बिक्री भी 10,097 यूनिट के साथ 58.61फीसदी बढ़ी। हालांकि हिमालयन, 650 ट्विन, गुरिल्ला और शॉटगन जैसे मॉडल इस बार पिछड़ गए। इनमें हिमालयन की 23.81फीसदी, 650 ट्विन की 48.91फीसदी, गुरिल्ला की 49.88फीसदी और शॉटगन की 42.62फीसदी की सालाना गिरावट रही। फिर भी कंपनी की कुल बिक्री बहुत मजबूत रही।

दिसंबर 2025 में रॉयल एनफील्ड ने कुल 93,177 यूनिटें बेचीं, जो दिसंबर 2024 के 67,891 यूनिट के मुकाबले 25,286 यूनिट ज्यादा हैं। यानी कंपनी ने सालाना आधार पर 37.24 फीसदी की दमदार ग्रोथ हासिल की। क्लासिक, बुलेट और हंटर ने लगातार तीसरी बार शीर्ष तीन पोजीशन पर कब्जा बनाए रखा और यह इस बात का संकेत है कि 350सीसी सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड की पकड़ अभी भी बेहद मजबूत है। इन आंकड़ों से साफ है कि कंपनी का 350सीसी पोर्टफोलियो भारतीय बाजार में लगातार भरोसे का प्रतीक बना हुआ है।

फरवरी में बढ़ेगी गर्मी, रबी फसलों पर मंडराया खतरा

- उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान सामान्य से अधिक, बारिश औसत से कम रहने का अनुमान

नई दिल्ली । भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने फरवरी महीने के लिए जारी मासिक पूर्वानुमान में चेतावनी दी है कि इस साल देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है, जबकि बारिश औसत से कम होने की संभावना है। खासतौर पर उत्तर-पश्चिम भारत में कम बारिश और बढ़ते तापमान से रबी की खड़ी फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई गई है। आईएमडी के अनुसार पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में फरवरी के दौरान अधिक तापमान के कारण रबी फसलों की वृद्धि तेज हो सकती है। इससे गेहूं और जौ जैसी फसलें समय से पहले पक सकती हैं, जिसे जबरन पकाव कहा जाता है। इसका नतीजा बालियों का आंशिक रूप से बंजर होना और दानों का हल्का रहना हो सकता है, जिससे कुल पैदावार घटने की आशंका है। सरसों, चना, मसूर और मटर जैसी फसलों में सामान्य से अधिक तापमान जल्दी फूल आने और समय से पहले पकने का कारण बन सकता है। इससे फलियां पूरी तरह विकसित नहीं होंगी और बीज छोटे रह सकते हैं। साथ ही गर्म मौसम में एफिड्स और अन्य चूसने वाले कीटों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है, जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, फूलगोभी और बंदगोभी जैसी सब्जियों में अधिक तापमान कंद, फूल और फल विकास को प्रभावित कर सकता है।

फलों में आम, सिट्रस, केला और अंगूर में जल्दी फूल आने, असमान फल लगने और फल झड़ने की संभावना बढ़ सकती है। आईएमडी ने बताया कि उत्तर भारत में बोया गया 80 प्रतिशत से अधिक गेहूं गर्मी सहन करने वाली किस्मों का है और सिंचाई सुविधाएं भी बेहतर हुई हैं। इसके बावजूद किसानों को मौसम के अनुसार फसल प्रबंधन और कृषि विभाग की सलाह पर अमल करने की जरूरत है।

बीएमडब्ल्यू ने इलेक्ट्रिक सेडान आई7 के साथ रचा नया इतिहास

नई दिल्ली ।

बीएमडब्ल्यू ने लग्जरी इलेक्ट्रिक कार बाजार में अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक सेडान आई7 के साथ नया इतिहास रच दिया है। 2.05 करोड़ रुपये की शुरुआती कीमत वाली यह कार बीएमडब्ल्यू इंडिया की लाइन-अप में सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान मानी जाती है। बीएमडब्ल्यू आई7की भारत में बिक्री 1,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर चुकी है, जो कि कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह उन ग्राहकों के लिए डिज़ाइन की गई है, जो हाई-पर्फॉर्मेंस, अत्याधुनिक तकनीक और अल्ट्रा-लक्जरी फीचर्स वाली इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं।

बीएमडब्ल्यू आई7 ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ हरदीप सिंह बरार के अनुसार, आई7 की बढ़ती बिक्री यह संदेश देती है कि भारत के प्रीमियम ग्राहक अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि बीएमडब्ल्यू आई7 सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो डिज़ाइन, लग्जरी और एक्शन में अपनी श्रेणी की सबसे अलग पहचान बनाती है। डिजाइन की बात करें तो आई 7 एक फ्यूचरिस्टिक लुक वाली कार है, जिसमें इल्यूमिनेटेड किडनी ग्रिल, प्रीमियम ड्यूल-हेडलैंप सेटअप और दमदार रोड प्रेजेंस मिलता है। इंटीरियर में 31-इंच 8के थिएटर स्क्रीन, मसाज और वेंटिलेशन वाली रियर एक्जीक्यूटिव सीटें, कर्व्ड डिजिटल डिस्प्ले और लक्जरी फिनिश इसे एक चलते-फिरते 5-स्टार लाउंज जैसा अनुभव देती हैं। बीएमडब्ल्यू इंडिया के लिए आई 7 उसकी इलेक्ट्रिक रणनीति का केंद्र मानी जा रही है।

कंपनी अब अपने ईवी पोर्टफोलियो का विस्तार तेज़ी से कर रही है। आई 7 की सफलता यह साबित करती है कि भारत में लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों का भविष्य बेहद उज्ज्वल है और ग्राहक अब नई तकनीक और टिकाऊ मोबिलिटी को अपनाने के लिए पहले से अधिक तैयार हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो बीएमडब्ल्यू आई7 कंपनी की 5वीं जेनरेशन ईड्राइव तकनीक से लैस है और 449 एचपी की पावर तथा 650 एनएम का टॉर्क जेनरेट करती है। यह कार मात्र 5.5 सेकंड में 0 से 100 किमी./घंटा की स्पीड पकड़ लेती है।

डिओ 125 स्कूटर का नया एक्स-एडिशन पेश

नई दिल्ली ।

दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा ने अपने लोकप्रिय 125सीसी स्कूटर सेगमेंट में डिओ 125 का नया एक्स-एडिशन पेश किया है। इसमें इंजन या परफॉर्मेंस से जुड़ा कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसके कॉस्मेटिक अपडेट इसे स्टैंडर्ड डिओ 125 से काफी अलग और ज्यादा स्पोर्टी बनाते हैं। होंडा डिओ 125 एक्स-एडिशन को दो नए आकर्षक रंगों में उतारा गया है, जिनमें पियर्ल सिरेन ब्लू और पियर्ल डीप ग्राउंड ग्रे शामिल हैं। यह डुअल-टोन कलर स्कीम स्कूटर को फंकी और यूथफुल अपील देती है। बॉडी पर दिए गए नए ग्राफिक्स और रेड कलर के अलॉय व्हील्स इसके लुक में जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट जोड़ते हैं। खासतौर पर लाल अलॉय व्हील्स इस स्कूटर को भीड़ से अलग पहचान दिलाते हैं और इसे एक स्पोर्टी कैरेक्टर देते हैं। फीचर्स के मामले में यह स्कूटर डिओ 125 के एच-स्मार्ट वैरिएंट जैसा ही है। इसमें टीएफटी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कॉल और एसएमएस अलर्ट, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। ये सभी सुविधाएं इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी प्रैक्टिकल बनाती हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 123.92सीसी का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 8.19 बीएचपी की पावर और 10.5 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन स्मूद परफॉर्मेंस और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। होंडा डिओ 125 एक्स-एडिशन के आने वाले हफ्तों में भारतीय बाजार में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 93,000 से 93,500 रुपये के बीच हो सकती है। स्पोर्टी डिजाइन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ यह स्कूटर युवाओं के लिए एक मजबूत विकल्प बनकर उभर सकता है। यह स्कूटर खासतौर पर युवा ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जो स्टाइल, टेक्नोलॉजी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन चाहते हैं।

बजट में खेलों पर भी जोर, 'खेलो इंडिया मिशन' होगा शुरु

प्रशिक्षण केंद्रों, कोचों और खेल ढांचे में व्यवस्थित विकास पर रहेगा जोर

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार के रविवार को पेश किये गये आम बजट में खेलों पर भी काफी जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए 'खेलो इंडिया मिशन' शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस मिशन का लक्ष्य अगले 10 साल में प्रशिक्षण केंद्रों, कोचों और खेल ढांचे में व्यवस्थित विकास कर नई प्रतिभाओं को सामने लाना रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि खेल क्षेत्र रोजगार, कौशल विकास और करियर के कई अवसर पैदा करता है। उन्होंने बताया कि साल 2017 में शुरू किए गए खेलो इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार अब इसे एक व्यापक और एकीकृत मिशन के रूप में लागू करना चाहती है, जिससे खेल क्षेत्र में और भी बदलाव आयें।

सीतारमण ने कहा कि खेलो इंडिया मिशन के तहत, प्राथमिक, मध्यवर्ती और विशिष्ट स्तर के प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा कोचों और सहायक स्टाफ का भी व्यवस्थित विकास किया जाएगा। इसमे खेल विज्ञान और आधुनिक तकनीक को प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा, देशभर में प्रतियोगिताओं और लीगों के आयोजन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, प्रशिक्षण और मुकाबलों के लिए खेल अवसंरचना को मजबूत किया जाएगा, इससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सामने आने के लिए बेहतर मंच और संसाधन मिलेगा।

कम कीमतों में उच्च गुणवत्ता के खेल सामान निर्माण की दिशा में भी सरकार काम करने जा रही है। इससे उपकरण डिजाइन, सामग्री विज्ञान, विनिर्माण अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस कार्यबल ने उच्च गुणवत्ता वाले कोच तैयार करने और उनके लिए लक्ष्य ओलंपिक पोडियम कार्यक्रम जैसी योजना शुरू करने पर जोर दिया है।

भारत की देविका ने थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन जीता

बैंकॉक (एजेंसी)। भारत की उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। देविका को इस टूर्नामेंट के महिला एकल के खिताबी मुकाबले में मलेशिया की गोह जिन वेई के मैच के बीच से हट जाने के बाद आसानी से अपना पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 खिताब हासिल को गया। देविका तब मैच में 21-8, 6-3 से आगे चल रही थी तभी मलेशिया की वेई हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण मुकाबले से हट गयीं। इससे देविका को अपने करियर का एक बड़ा खिताब मिल गया। दो वर्षों से फॉर्म और फिटनेस के लिए संघर्ष कर रही वेई ने इससे पहले के मैच में भी थकान की शिकायत की थी। देविका ने फाइनल में तेज शुरुआत की। उन्होंने अपने दमदार रिटर्न और बेहतरीन स्ट्रोक के दम पर 4-0 की बढ़त बना ली। वहीं एक नेट कॉर्ड की बदौलत वेई ने अपना पहला अंक हासिल किया।वह पिछले सत्र में इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 में उपविजेता रही थी जबकि 2024 में चार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। विश्व रैंकिंग में 63वें स्थान पर बरकार 20 साल की देविका बेंगलुरु के पादुकोण-द्रविड़ सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में प्रशिक्षण ले रही हैं। वह पिछले कुछ समय से ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु से भी खेल की टिप्स ले रहीं थीं।

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 : भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने किया चित, 58 रनों से जीता मुकाबला

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर सिक्स मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए 58 रनों से हरा दिया है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेदांत त्रिवेदी के अर्धशतक की बदलौत एक गेंदें शेष रहते सभी 10 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान को 253 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में पाकिस्तान 194 रनों पर ढेर हो गई। त्रिवेदी ने 98 गेंदों पर 2 चौकों और एक छक्के की मदद से 68 रन बनाए जिससे भारत 250 का आंकड़ा पार कर पाया। वैभव सूर्यवंशी 22 गेंदों पर मात्र 30 रन ही बना पाए जबकि ओपनर ऑरोन जॉर्ज ने भी 16 रन की छोटी पारी खेली। कप्तान आयुष म्हात्रे खाता भी नहीं खोल सके।

प्लेइंग 11

भारत अंडर-19 : एरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), वेदांत त्रिवेदी, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन

पाकिस्तान अंडर-19 : हमजा जहूर (विकेटकीपर), समीर मिन्हास, उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हुजैफा अहसन, अली हसन बलूच, अब्दुल सुभान, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, अली रजा

वैभव सूर्यवंशी को नेशनल टीम में शामिल करने का समय आ गया: सबा करीम

ओपन में डेब्यू के बाद पहला मेलबर्न फाइनल भी था।

मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) (एजेंसी)। वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्काराज ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतकर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। 22 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी ने फाइनल में अपने प्रतिद्वंद्वी और सर्बियाई दिग्गज नोवाक जोकोविच को हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और अपना सातवां बड़ा खिताब जीता।

वर्ल्ड नंबर 1 ने 10 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन जोकोविच को एक रोमांचक चार-सेट के फाइनल (2-6 6-2 6-3 7-5) में हराकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। अल्काराज ने फाइनल तीन घंटे और दो मिनट में जीता। ATP के अनुसार अल्काराज ओपन एरा में करियर ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाले छठे खिलाड़ी भी बन गए हैं। गौरतलब है कि यह अल्काराज का ऑस्ट्रेलियन ओपन में डेब्यू के बाद पहला मेलबर्न फाइनल भी था।

ATP के अनुसार 21वीं सदी में केवल चार खिलाड़ियों ने करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया है। जोकोविच ने 2016 में ऐसा किया था, उसके बाद राफेल नडाल (2010) और रोजर फेडरर (2009) का नंबर आता है। इसके साथ ही 22 वर्षीय अल्काराज ने दिग्गजों के बीच अपनी जगह पक्की कर ली है। पुरुषों में ओपन एरा में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज (22 साल और 272 दिन) रॉड लेवर (24 साल और 32 दिन), राफेल नडाल (24 साल और 102 दिन), रोजर फेडरर (27 साल और 303 दिन), नोवाक जोकोविच (29 साल और 15 दिन) और आंद्रे अगासी (29 साल और 68 दिन) हैं।

ATP के अनुसार लेवर ने 1962 में एक शौकिया खिलाड़ी के तौर पर और 1969 में ओपन एरा में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। वर्ल्ड नंबर 1 ओपन एरा में सात बड़े सिंगल्स टाइटल जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं, जो ब्योर्न बोर्ग से आगे हैं, जिन्होंने 1979 में रोलैंड गैरोस में सातवां बड़ा टाइटल जीता था। 2022 में अल्काराज ने US ओपन में अपना पहला बड़ा टाइटल जीता और इस जीत के साथ वह PIF ATP रैंकिंग (1973 से) में सबसे कम उम्र के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। इस स्पेनिश खिलाड़ी ने 2023 में अपनी पहली विंबलडन ट्रॉफी जीती और 2024 ग्रैंड स्लैम इवेंट में अपने टाइटल का बचाव किया। रोलैंड गैरोस में अल्काराज 2024 और 2025 में विजयी रहे।

बुमराह ने अपने टी20 करियर का सबसे महंगा ओवर किया

तिरुवनंतपुरम। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम टी20 में असफल रहे। बुमराह इस मैच में सबसे महंगे साबित हुए। वह 58 रन देने के बाद भी कोई विकेट नहीं ले पाये। ये पहली बार रहा जब बुमराह ने किसी मैच में इतने अधिक रन दिये। इससे पहले का उनका सबसे महंगे मैच 2021 का आईपीएल रहा था। तब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चार ओवर में 56 रन देकर केवल एक विकेट लिया था। बुमराह ने इस अंतिम मैच में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अपना सबसे महंगा ओवर भी किया। इसमें बुमराह ने 22 रन दिये। वहीं इससे पहले बुमराह का सबसे महंगा ओवर साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ आया था, तब उन्होंने एक ही ओवर में 21 रन दिए थे। बुमराह के अलावा अन्य भारतीय गेंदबाज भी काफी महंगे रहे। अर्शदीप सिंह ने 51 रन दिये हालांकि उन्होंने पांच विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने 15 रन, वरुण चक्रवर्ती ने एक विकेट लेकर 36 रन वह अक्षर पटेल ने तीन विकेट लेकर 33 रन दिये। बुमराह और अर्शदीप के इस प्रकार के महंगे ओवरों से टी20 विश्वकप से पहले भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। भारत ही नहीं यहां अंतिम मैच में कीवी गेंदबाजों की भी जमकर कुटाई हुई। कीवी गेंदबाज जेकब डफी, काइल जेमिसन और मिचेल सैंटनर ने 50 रनों से अधिक दिये। सैंटनर के ओवर में 60 रन बने।

अर्शदीप टी20 में सबसे अधिक रन देकर पांच विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बने

तिरुवनंतपुरम। युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पांच विकेटों की सहायता से भारतीय क्रिकेट टीम ने पांचवे और अंतिम टी20 में न्यूजीलैंड को 46 रनों से हरा दिया।

इसी के साथ ही भारतीय टीम ने ये सीरीज 4-1 से जीती पर मैच में पांच विकेट लेने के बाद भी अर्शदीप के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हुआ जिसे वह याद नहीं रखना चाहेंगे। अर्शदीप इसी के साथ ही किसी अंतरराष्ट्रीय टी20 मुकाबले में सबसे ज्यादा रन देकर 5 या उससे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के अल्जारी जोसेफ के नाम दर्ज था। जोसेफ ने जोहानसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साल 2023 में 40 रन देकर 5 विकेट लिए थे। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लुंगी एंगिडी ने साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल में 39 रन देकर 5 विकेट लिए थे। गौरतलब है कि अर्शदीप टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गये हैं। साल 2022 में डेब्यू करने के बाद से ही अर्शदीप ने 76 मैचों में 118 विकेट लिए हैं। यह पहला मौका था, जब अर्शदीप ने एक पारी में 5 विकेट लिए।

वैभव यूथ एकदिवसीय में सबसे अधिक रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बने

बुलावायो। भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 विश्व कप 2026 के सुपर-6 राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ हुए मुकाबले में 11 रन बनाते ही एक अहम उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली। अब उनके यूथ एकदिवसीय में 1150 रन हो गये हैं। इस मैच के दौरान जैसे ही वैभव ने अपने 11 रन पूरे किए। वह भारत के लिए यूथ एकदिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में शामिल हो गये हैं। वैभव ने अपनी पारी के दौरान 22 गेंदों का सामना करते हुए कुल 30 रन बनाए जिसमें 5 चौके और एक छक्का शामिल था। अब वैभव की नजरें यूथ एकदिवसीय में सबसे रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर टिक गई हैं। वह जल्द ही विजय जोल के 1404 रन और यशस्वी जयसवाल के 1386 रन के रिकार्ड भी तोड़ सकते हैं।यूथ एकदिवसीय में सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज तन्मय श्रीवास्तव हैं उनके नाम 1316 रन हैं।

भारतीय टीम को उसी की धरती पर हराना बेहद कठिन काम: सेंटनर

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कप्तान मिचेल सेंटनर ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-4 से मिली करारी हार के बाद कहा कि भारतीय टीम को उसी की धरती पर हराना बेहद कठिन काम है क्योंकि वह बखूबी जानती है कि अपने मैदानों में किस प्रकार खेलना है। इस सीरीज में भारतीय टीम के सामने कीवी टीम बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी में भी टिक नहीं पायी। भारतीय टीम सीरीज में केवल एक ही मैच में हारी थी। पहले तीन मैच जीतने के बाद भारतीय टीम को चौथे मैच में हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम ने अंतिम मैच में 46 रनों की जीत के साथ ही सीरीज अपने नाम की। भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखते हुए सेंटनर की चिन्ताएं बढ़ गयी हैं क्योंकि अब उसे 7 फरवरी से होने वाले टी20 विश्वकप में भी भारतीय टीम से उसी की धरती पर खेलना है। विश्वकप संयुक्त रुप से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा।

सेंटनर ने कहा, पूरी सीरीज को देखें तो हमें काफी सकारात्मक बातें भी सीखने को मिलीं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भारतीय टीम काफी अच्छी है। उसे इन हालातों में हराना बहुत कठिन है। ये सीरीज कुल मिलाकर मनोरंजक रही। साथ ही कहा कि जब आपको पूरी सीरीज में चुनौती मिलती है तो यह हमेशा अच्छी बात होती है। गेंदबाजों और बल्लेबाजों पर दबाव पड़ता है और उससे आप उससे सीखते हैं। परिणाम भले ही हमारे पक्ष में भले ही नहीं रहे पर हमें हर एक मैच से कुछ न कुछ सीखने को मिला। अब न्यूजीलैंड टीम आठ फरवरी से टी20 विश्वकप में उतरेगी। कीवी टीम इसमें ग्रुप डी में शामिल है, जिसमें अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और यूएई हैं। न्यूजीलैंड को अपने मैच भारतीय धरती पर खेलने हैं। वहीं सेंटनर ने कहा कि विश्वकप को लेकर उन्हें काफी सुधार करने होंगे। गेंदबाजी में हमें विरोधी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने के तरीके तलाशने होंगे।

अंडर-19 विश्वकप में भी भारत-पाक कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया

बुलावायो (जिम्बाब्वे)। भारत और पाकिस्तान की टीमों ने आज यहां आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 के सुपर 6 ग्रुप 2 मैच में हाथ नहीं मिलाया। टॉस के बाद भारतीय अंडर-19 कप्तानी आयुष म्हात्रे और पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ हाथ मिलाये बिना ही वापस हो गये। इस प्रकार एशेया कप में जिस प्रकार भारतीय सीनियर टीम ने पाक खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। वही सिलसिला इस मैच में भी बरकरार रहा। भारतीय सीनियर टी10 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साल 2025 एशिया कप के दौरान अपने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से इंकार कर दिया था, तब से ही भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैचों में टॉस के दौरान हाथ न मिलने का सिलसिला जारी है। भारत ए टीम के कप्तान ने भी एशिया कप। इससे के अलावा महिला विश्वकप में भी भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाक कप्तपान से हाथ नहीं मिलाया था। भारतीय टीम के पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाने का कारण पाक का पहलगाम आतंकी हमले में शामिल होना रहा है। इसके बाद भारतीय सेना ने पाक में आतंकी ठिकानों को धवस्त कर दिया था।

ईशान को अंतिम टी20 में विकेटकीपर बनाने का कारण सूर्यकुमार ने बताया

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम टी20 मैच में ईशान किशन के विकेटकीपिंग किये जाने के कारणों का खुलासा किया है। सूर्या ने खुलासा किया कि सीरीज शुरू होने से पहले ही तय हो गया ता कि संजू पहले तीन मैच में विकेट कीपिंग करेंगे, वहीं आखिरी दो मुकाबलों में ईशान किशन को मौका मिलेगा। सूर्या ने कहा, तिलक वर्मा के नहीं होने की वजह से संजू सैमसन और ईशान दोनो को ही शामिल किया गया था। हमने सीरीज से पहले ही तय कर लिया था कि संजू तीन मैचों में विकेटकीपिंग करेंगे और ईशान अंतिम दो मैचों में ये जिम्मेदारी संभालेंगे। ईशान फिट नहीं होने के कारण पिछले मैच से बाहर थे। ईशान की शतकीय पारी के लिए भी सूर्या ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि टीम उनके कौशल के बारे में पहले से ही जानती थी। भारतीय कप्तान ने कहा, फ़हम हमेशा जानते थे कि वह क्या कर सकते हैं और हमने इस सीरीज से पहले घरेलू क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी देखी थी। हम चाहते थे कि वह उसी तरह बल्लेबाज करें और अपनी पहचान न बदलें। वह घरेलू क्रिकेट में पारी शुरुकर रहे थे, और यहां वह नंबर तीन पर बल्लेबाज कर रहे थे। हम चाहते थे कि वह गेम-चेंजर बनें, उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की उससे हमें बेहद खुशी हुई है ' ईशान को टीम में जगह तिलक वर्मा के चोटिल होने के कारण मिली थी और उन्होंने अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए शतक बनाया। ऐसे में माना जा रहा है कि तिलक की टीम में वापसी होते ही सैमसन को बाहर होना पड़ेगा क्योंकि कीवी टीम के खिलाफ पांच मैचों में सैमसन बूरी तरह से असफल रहे थे।

ईशान किशन बनाम संजू सैमसन : ओपनिंग स्लॉट पर कब होगा फैसला, सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय टी20 टीम में ओपनिंग स्लॉट को लेकर चल रही बहस अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया है कि ईशान किशन और संजू सैमसन में से कौन ञ्च20 वर्ल्ड कप 2026 में ओपनिंग करेगा, इसका अंतिम फैसला 7 फरवरी को लिया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीत के बाद स्यड्ढ ने टीम कॉम्बिनेशन, बल्लेबाजी अप्रोच और घरेलू वर्ल्ड कप के दबाव को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी।

ओपनिंग स्लॉट पर सस्पेंस बरकरार

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के बाद ब्रॉडकास्टर से बातचीत में सूर्यकुमार यादव ने माना कि ओपनर को लेकर चयन की दुविधा अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों ही प्लेइंग XI के मजबूत दावेदार हैं और इस मुद्दे पर स्पष्टता 7 फरवरी को सामने आएगी। कप्तान के मुताबिक, टीम मैनेजमेंट हर पहलू पर विचार कर रही है।

तिलक वर्मा की वापसी से बढ़ी मुश्किल

SKY ने यह भी बताया कि तिलक वर्मा की फिटनेस और फॉर्म चयन प्रक्रिया को और चुनौतीपूर्ण बना रही है। उनके अनुसार, तिलक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और वापसी के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्क्वाड के सभी 15 खिलाड़ी अंतिम एकादश में जगह बनाने के दावेदार हैं, जिससे सिलेक्शन कॉल और भी मुश्किल हो गया है।

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का रणनीतिक प्लान

सूर्यकुमार यादव ने भारत की संभावित रणनीति पर बात करते हुए कहा कि मौजूदा टी20 क्रिकेट में आक्रामक टॉप ऑर्डर बेहद जरूरी है। उन्होंने संकेत दिए कि टीम को नंबर 7 या 8 तक एक अतिरिक्त स्पेशलिस्ट बल्लेबाज की जरूरत हो सकती है। कप्तान के मुताबिक, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल मिलकर 16 ओवर डाल सकते हैं, जिससे बल्लेबाजी को गहराई देने का मौका मिलता है।

ऑलराउंडर्स से मिल रही है फ्लेक्सिबिलिटी

SKY ने बताया कि हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और जरूरत पड़ने पर अभिषेक शर्मा गेंदबाजी में अतिरिक्त विकल्प देते हैं। इससे टीम सात बल्लेबाज और ऑलराउंडर्स के साथ एक मजबूत कॉम्बिनेशन बना सकती है, जो वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में बेहद अहम साबित हो सकता है।

घरेलू वर्ल्ड कप का दबाव और उत्साह

भारत में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप को लेकर सूर्यकुमार यादव ने कहा कि घरेलू परिस्थितियों में खेलना दबाव जरूर लाता है, लेकिन यही दबाव खेल को रोमांचक बनाता है। उन्होंने माना कि लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतना ऐतिहासिक चुनौती है, लेकिन इसे वह सकारात्मक दबाव और बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देख रहे हैं।

निडर बल्लेबाजी से कप्तान खुश

न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 की सीरीज जीत के बाद कप्तान ने भारतीय बल्लेबाजों की निडर सोच की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी अपनी स्वाभाविक शैली में खेलते हैं और उन्होंने सभी को उसी अप्रोच पर टिके रहने के लिए प्रोत्साहित किया है।

'पहली गेंद पर छक्का भी सही फैसला हो सकता है'

SKY के मुताबिक, टी20 क्रिकेट में हालात के हिसाब से फैसले लेने जरूरी हैं। अगर पिच और कंडीशन इजाजत देती है, तो पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने में कोई बुराई नहीं है। कप्तान का मानना है कि खिलाड़ियों का यह बेखौफ रवैया उनकी कप्तानी को आसान बनाता है।

पांड्या डेथ ओवरों में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने

तिरुवनंतपुरम। ऑलराउडर हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में 17 गेंदों पर ही 42 रन बनाकर एक नया रिकार्ड अपने नाम किया है। इस पारी में पांड्या का स्ट्राइक रेट 247.06 का रहा। इससे वह अन्य खिलाड़ियों से अलग नजर आये। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी इस आक्रामक पारी से पांड्या ने अंतिम ओवरों (डेथ ओवरों) में 1000 रन बनाने का एक नया रिकार्ड अपने नाम किया है। पांड्या के नाम अब अंतिम ओवरों में 1030 रन हो गये हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर के नाम अंतिम ओवरों में 986 रन हो गये हैं और वह दूसरे नंबर पर है जबकि अफगानिस्तान के मो नबी 973 रनों के साथ ही तीसरे नंबर पर हैं। पांड्या जब बल्लेबाजी के लिए आये थे। तब भारतीय टीम ने 14.3 ओवर में 3 विकेट पर 185 रन बनाये थे। वहीं इसेक बाद पांड्या ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम का 20 ओवर में 271 रन तक पहुंचा दिया जिससे कीवी टीम पर दबाव आया और वह 272 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 225 रनों पर ही सिमट गयी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

ईरान के गृहमंत्री पर अमेरिका ने लगाया नया प्रतिबंध

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी पर प्रतिबंध लगाए। उन पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों को दबाने का आरोप लगाया गया है, जिनमें तेहरान की धार्मिक नेतृत्व वाली सरकार को चुनौती दी गई थी। ये पाबंदियां दमनकारी कार्रवाई को लेकर उच्च पदस्थ अधिकारियों को निशाना बनाते हुए अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा की गई नवीनतम कार्रवाई हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि मोमेनी ने ईरान के उन कानून लागू करने वाले सुरक्षा बलों की निगरानी की है, जो हजारों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। ईरान में आर्थिक संकट के कारण दिसंबर के उत्तरार्द्ध में प्रदर्शन शुरू हुए, जो बाद में इस्लामी गणराज्य के लिए एक चुनौती में बदल गए। इसके बाद दमनकारी कार्रवाई शुरू हुई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस कार्रवाई में 6,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। ईरानी अधिकारी और सरकारी मीडिया बार-बार प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी बता रहे हैं। यूरोपीय संघ ने बृहस्पतिवार को मोमेनी के साथ-साथ ईरान की न्यायिक प्रणाली के सदस्यों और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए। यूरोपीय संघ ने कहा, वे सभी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के हिंसक दमन और राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की मनमानी गिरफ्तारी में शामिल थे। यूरोपीय संघ ने ईरान के अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल करने पर सहमति जताई है, जो काफी हद तक एक प्रतीकात्मक कदम है तथा तेहरान पर दबाव को और बढ़ायेगा। अमेरिका द्वारा लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों में राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वोच्च परिषद के सचिव का नाम भी शामिल है, जिन पर अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरानी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का आह्वान करने वाले शुरुआती अधिकारियों में से एक होने का आरोप लगाया है।

अदानी समूह के साथ विवादों को निपटाने के लिए ब्रिटिश फर्म की मदद ले रहा बांग्लादेश

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश ने शुक्रवार को बताया कि उसने अदानी पावर लिमिटेड के साथ कोयले की कीमत और बिजली दरों को लेकर चल रहे विवादों में अपने सरकारी बिजली विकास बोर्ड (बीपीडीबी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ब्रिटिश कानूनी फर्म को नियुक्त किया है। बीपीडीबी के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने लंदन स्थित 3वीपी को सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआइएसी) में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया है। किंग्स काउंसिल फरहाज खान के नेतृत्व वाली 3वीपी फर्म कई महीनों से अदानी सौदे पर एक राष्ट्रीय समीक्षा समिति को सलाह दे रही है। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ब्रिटिश फर्म को नियुक्त करने का कदम तब आया जब अदानी पावर ने पिछले साल सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में मध्यस्थता शुरू की थी।

ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को न्यूजीलैंड की ना, निमंत्रण किया अस्वीकार

बेलिंग्टन, एजेंसी। न्यूजीलैंड ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड आफ पीस में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी। ट्रंप ने पिछले सप्ताह ही अपने बोर्ड आफ पीस की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य गाजा में चल रहे अस्थिर युद्धविराम को मजबूत करना था, लेकिन अब उनका मानना है कि यह बोर्ड अन्य वैश्विक शक्तियों से संबंधित व्यापक भूमिका निभाएगा। उन्होंने दर्जनों अन्य विश्व नेताओं को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि तुर्किये, मिस्त्र, सऊदी अरब और कतर और इंडोनेशिया इस बोर्ड में शामिल हो चुके हैं, लेकिन वैश्विक शक्तियां और अमेरिका के पारंपरिक पश्चिमी सहयोगी अधिक सतर्क रहे हैं। लक्सन ने एक ईमेल में बयान जारी कर कहा कि वर्तमान स्वरूप में बोर्ड आफ पीस में शामिल न होने का निर्णय लिया गया है।

नेपाल ने अपने बलिदानियों को किया याद, हर साल मनाया जाता है शहीद सप्ताह

काठमांडु, एजेंसी। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सभी राजनीतिक दलों और आम जनता से अपील की कि वे उन शहीदों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए अपने प्रयास समर्पित करें, जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। नेपाल हर वर्ष स्थानीय विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार माघ 10 से 16 तक शहीद सप्ताह मनाता है और इसका अंतिम दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इस वर्ष शुक्रवार, 30 जनवरी को पड़ा है। इस दिन शहीद शुक्लराज शास्त्री, धर्म भक्त, दशरथ चंद और गंगा लाल के श्रेष्ठ बलिदान को याद किया जाता है। साथ ही उन अन्य शहीदों के योगदान को भी याद किया जाता है।

फर्जी जॉब पोस्टिंग का जाल, फिर महिलाओं को बनाता था शिकार

कनाडा में भारतीय मूल के व्यक्ति की शर्मनाक करतूत

टोरंटो , एजेंसी। कनाडा से एक बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां भारतीय मूल के एक पंजाबी व्यक्ति ने नौकरी का झांसा देकर कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया। आरोपी फर्जी कंपनी का मालिक या रिक्रूटर बनकर ऑनलाइन वेबसाइट्स पर नौकरी के विज्ञापन डालता था और फिर मिलने के बहाने महिलाओं के साथ जबरदस्ती करता था। कनाडा पुलिस ने इस मामले में 47 साल के तजिंदर धालीवाल को गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति खासतौर पर लड़कियों को ही निशाना बनाता था और आसान नौकरी का लालच देकर उन्हें बुलाता था।

ऑनलाइन जॉब विज्ञापन से शुरू होता था खेल : पुलिस के मुताबिक, तजिंदर धालीवाल कनाडा की लोकप्रिय क्लासिफाइड वेबसाइट जैसे प्लेटफॉर्म पर नौकरी के विज्ञापन देता था। इन विज्ञापनों में डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी बताई जाती थी, सिर्फ लड़कियों की मांग होती थी साथ ही किसी तरह की योग्यता या अनुभव नहीं मांगा जाता था। फ्रेशर्स को खास तौर पर टारगेट किया जाता था। इससे लड़कियों को लगता था कि नौकरी आसानी से मिल जाएगी।

सुनसान इंडस्ट्रियल इलाकों में ले जाकर करता था दरिंदगी : कनाडा पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी इंटरव्यू के नाम पर महिलाओं को मिल्टन और हॉल्टन हिल्स जैसे दूर-दराज के इंडस्ट्रियल पार्किंग एरिया में ले जाता था। ये जगहें इतनी सुनसान होती थीं कि आसपास कोई मदद नहीं मिल पाती और चीखने-चिल्लाने पर भी कोई सुनने वाला नहीं होता। पुलिस का कहना है कि तजिंदर जानबूझकर ऐसी जगहें चुनता था, ताकि पीड़ित महिलाएं पूरी तरह असहाय हो जाएं। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब दो महिलाओं ने हॉल्टन रीजनल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पहली पीड़िता की आपबीती : एक लड़की ने बताया कि उसने नौकरी के विज्ञापन पर कॉल किया। तजिंदर ने उसे बुलाया, टैक्सी में बैठाया और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की।

दूसरी पीड़िता ने बताया डरावना सच : दूसरी लड़की ने बताया कि दिसंबर 2025 में उसने नौकरी के लिए कॉल किया था।

तजिंदर ने उसे जॉब वेबसाइट दिखाने के बहाने टैक्सी में बैठाया, ब्रैम्पटन से कई किलोमीटर दूर एक इंडस्ट्रियल साइट पर ले गया। उसने पहाड़ी और सुनसान इलाके में गाड़ी रोक दी। जब लड़की ने वजह पूछी तो आरोपी ने कहा,मेरे साथ रिलेशन बनाओ, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। इसके बाद उसने लड़की के साथ जबरदस्ती की।

26 जनवरी को गिरफ्तारी, फोटो जारी : लगातार जांच और सबूत जुटाने के बाद 26 जनवरी 2026 को ब्रैम्पटन पुलिस ने तजिंदर धालीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उस पर रेप, नौकरी के बदले यौन सेवा मांगने और महिलाओं को धोखे से फंसाने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गईं। पुलिस ने आरोपी की तस्वीर भी सार्वजनिक की, ताकि अगर कोई और पीड़िता उसके जाल में फंसी हो तो वह आगे आकर शिकायत दर्ज करा सके।

24 घंटे में जमानत, लोगों में गुस्सा : पुलिस के मुताबिक, कनाडा में रेप से जुड़े कानून अपेक्षाकृत नरम हैं। इसी कारण 27 जनवरी को कोर्ट में पेशी के बाद सिर्फ 24 घंटे में आरोपी को जमानत मिल गई। इस फैसले से कनाडा की स्थानीय और प्रवासी कम्युनिटी में भारी नाराजगी है।

कम्युनिटी की मांग ङ्क सख्त कानून हों : स्थानीय लोगों का कहना है– रेप एक बेहद गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में जमानत आसानी से नहीं मिलनी चाहिए और प्रवासियों से जुड़े अपराधों पर कड़े नियम बनाए जाने चाहिए। लोगों का मानना है कि अगर सख्ती नहीं होगी, तो ऐसे अपराधी कानून का फायदा उठाकर बार-बार बच निकलेंगे।

यूएन प्रमुख गुटेरस का बड़ा बयान; भारत- ईयू समझौते का दिया हवाला

जिनेवा , एजेंसी। भारत और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के बीच हुए व्यापार समझौते का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने बहुध्रुवीय व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि दुनिया एक या दो शक्तियों से नहीं चलेगी। उन्होंने अमेरिका और चीन का परोक्ष संदर्भ देते हुए यह बात कही। गुटेरस ने कहा कि हालिया भारत-ईयू व्यापार समझौते से बहुत सकारात्मक उम्मीदें हैं और यह वैश्विक बहुध्रुवीयता में योगदान दे सकता है।यूएन महासचिव गुटेरस ने 2026 के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए यहां गुरुवार को पत्रकारों से कहा, वर्तमान समय में यह स्पष्ट है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। हमारा और कई लोगों का भी भविष्य के संदर्भ में विचार है कि दो ध्रुव हैं- एक अमेरिका केंद्रित और एक चीन केंद्रित। उन्होंने कहा, अगर हम एक स्थिर दुनिया चाहते हैं और अगर हम ऐसी दुनिया चाहते हैं, जिसमें शांति कायम रह सके, जिसमें व्यापक विकास हो सके और जिसमें अंतत हमारे मूल्य कायम रहें तो हमें बहुध्रुवीयता का समर्थन करने की जरूरत है। यूएन प्रमुख अमेरिका और चीन का परोक्ष जिक्र करते हुए

कहा, वैश्विक समस्याओं का समाधान एक ही ताकत का हुकुम चलने से नहीं होगा। न ही उनका समाधान दो शक्तियों द्वारा दुनिया को प्रतिद्वंद्वी प्रभाव क्षेत्रों में बांटने से होगा।

अंतरराष्ट्रीय कानून के खुलेआम उल्लंघन जता चुके हैं चिंता : बता दें कि गुटेरस ने कुछ दिन पहले भी अंतरराष्ट्रीय कानून के खुलेआम उल्लंघन पर चिंता जताई थी। उन्होंने 15 जनवरी को 193 सदस्यीय महासभा में कुछ देशों की ओर से अंतरराष्ट्रीय कानून का खुले तौर पर उल्लंघन किए जाने की निंदा की थी और कहा था कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर कोई ऐसा मेन्यू नहीं है, जिसमें से अपनी पसंद का नियम चुना जा सके। उनका यह बयान वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई, 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले और अन्य भू-राजनीतिक चुनौतियों की पृष्ठभूमि में आया था। गुटेरस का यूएन महासचिव के रूप में यह दूसरा पांच वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर, 2026 को समाप्त होगा।

जेल से छूटते ही प्रिंस एंड्रयू ने एपस्टीन को बकिंघम पैलेस में किया गया था आमंत्रित

वाशिंगटन, एजेंसी। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस एंड्रयू और दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के रिश्तों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए नए दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि एंड्रयू ने साल 2010 में एपस्टीन को नजरबंदी से रिहा होने के तुरंत बाद बकिंघम पैलेस में आमंत्रित किया था। ईमेल्स के जरिए सामने आई इस बातचीत में पता चला है कि राजा चार्ल्स तृतीय के भाई एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर ने एपस्टीन को महल में एकांत और निजी समय बिताने का प्रस्ताव दिया था। अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार शुक्रवार लाखों नए पन्नों का दस्तावेज सार्वजनिक किया। जिसमें मध्य लंदन स्थित शाही निवास (बकिंघम पैलेस) का कथित निमंत्रण का खुलासा हुआ है। एपस्टीन को नजरबंदी से रिहा होने के तुरंत बाद बकिंघम पैलेस में आमंत्रित किया था। एक संदेश के अनुसार, एपस्टीन ने 27 सितंबर, 2010 को लंदन में प्रवास के दौरान एंड्रयू से संपर्क किया और लिखा,

आप मुझे किस समय चाहेंगे... हमें कुछ निजी समय भी चाहिए होगा। एंड्रयू ने जवाब दिया कि वह अभी स्कॉटलैंड छोड़ रहे हैं और आगे कहा, हम बकिंघम पैलेस में डिनर कर सकते हैं और काफी एकांत का आनंद ले सकते हैं। इसके ठीक दो दिन बाद एंड्रयू ने फिर से ईमेल भेजा। उन्होंने लिखा, आपका बकिंघम पैलेस आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप जिसके साथ भी आएं, मैं शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक यहां मुफ्त में मौजूद रहूंगा। लंदन स्थित जिस शाही निवास एपस्टीन को आमंत्रित किया गया, वह उस समय दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का लंदन स्थित आधिकारिक निवास था। हालांकि, दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं है कि महल में कभी कोई रात्रिभोज आयोजित हुआ था।

'रशियन लड़कियों' से संबंध से बिल गेट्स को हुआ था यौन रोग? एपस्टीन फ़ाइलें में चौंकाने वाला दावा

वॉशिंगटन , एजेंसी। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार बिल गेट्स एक बार फिरजेफरी एपस्टीन मामले की वजह से सुर्खियों में हैं। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा सार्वजनिक किए गए नए दस्तावेजों ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पर ऐसे आरोप लगाए हैं जो न केवल सनसनीखेज हैं, बल्कि उनकी निजी छवि पर भी गहरे सवाल खड़े करते हैं। हालांकि, ये तमाम दावे अभी तक सिर्फ कागजों तक सीमित हैं और इनके पीछे कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है।

मेलिंडा गेट्स का जिक्रः सबसे गंभीर आरोप यह है कि गेट्स कथित तौर पर एंटीबायोटिक्स की तलाश में थे ताकि वे अपनी तत्कालीन पत्नी मेलिंडा को भी अनजाने में दवा दे सकें। सबूत मिटाने की कोशिशः एपस्टीन ने यह भी लिखा कि गेट्स ने उससे इस मामले से संबंधित पुराने

संवाद हटाने का अनुरोध किया था। गेट्स खेमे का पलटवारः यह सिर्फ एक कुंठित अपराधी की खुन्नस है बिल गेट्स के प्रतिनिधियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे चरित्र हनन का प्रयास बताया है। प्रवक्ता के अनुसार, ये दस्तावेज सिर्फ यह साबित करते हैं कि जब गेट्स ने एपस्टीन से दूरी बना ली थी, तो वह बौखला गया था। एपस्टीन अपनी नाराजगी निकालने और गेट्स को बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहा था।

न्याय विभाग की सफाई और पुरानी तस्वीरों का साया : अमेरिकी प्रशासन ने अब तक एपस्टीन मामले से जुड़ी करीब 30 लाख फाइलों और लाखों तस्वीरों को जनता के सामने रखा है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी फाइल में नाम होने का मतलब यह कतई नहीं है कि वह व्यक्ति अपराधी है। इन दस्तावेजों के साथ कुछ पुरानी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें एपस्टीन एक साथ नजर आ रहे हैं। गेट्स पहले भी कई बार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर चुके हैं कि एपस्टीन से मिलना उनकी एक बड़ी भूल थी और उन्हें इसका गहरा पछतावा है।

मेलिंडा गेट्स और तलाक का वो अनकहा सच : गौरतलब है कि बिल और मेलिंडा गेट्स का 27 साल पुराना रिश्ता 2021 में टूट गया था। उस वक्त मेलिंडा ने संकेत दिया था कि एपस्टीन के साथ बिल की बढ़ती नजदीकी और कुछ निजी कारण इस अलगाव की बड़ी वजह थे। हालांकि, उन्होंने कभी भी इन स्त्रिष्ठ या रूसी महिलाओं जैसे आरोपों का खुलकर जिक्र नहीं किया।

बेरहम मां! 10 माह के मासूम पर सैंकड़ों बार सुई से हमला

बीजिंग, एजेंसी। दक्षिण-पश्चिमी चीन से सामने आई एक घटना ने इंसानियत को झकझोर दिया है। महज 10 महीने के एक बच्चे के शरीर पर सैकड़ों बार सुई चुभोने का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि यह क्रूरता किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि बच्चे की अपनी मां ने की थी। हॉन्गकॉन्ग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके शरीर पर सुई चुभने के असंख्य निशान पाए। मामला युन्नान प्रांत के एक काउंटी अस्पताल का है, जहां बच्चे को तेज बुखार और झटकों की शिकायत के साथ लाया गया था।

इलाज के नाम पर अमानवीय तरीका : डॉक्टरों की शुरुआती जांच में सामने आया कि बच्चे के सिर, गर्दन, धड़ और पैरों पर काले पपड़ी जैसे घाव थे। आगे की पड़ताल में यह चौंकाने वाला सच सामने आया कि बच्चे की मां कथित तौर पर घरेलू इलाज और सजा के तौर पर उसके शरीर में सुई चुभोती थी। अनुमान है कि यह हरकत 500 से 600 बार दोहराई गई। हालात तब और गंभीर हो गए जब जूते सिलने में इस्तेमाल होने वाली एक सुई बच्चे की गर्दन में टूटकर रीढ़ के पास फंस गई। इसके बाद डॉक्टरों को जटिल सर्जरी करनी पड़ी।

डॉक्टरों के लिए भी चुनौती : शिन्हुआ अस्पताल के वरिष्ठ स्पाइन सर्जन डॉ. सुई वेनयुआन ने बताया कि सर्जरी बेहद जोखिम भरी थी। सुई की बनावट और स्थिति स्पष्ट न होने के कारण जरा-सी चूक से बच्चे की नसों और आसपास के ऊतकों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता था। सभी जरूरी जांचों के बाद ऑपरेशन किया गया, जो सफल रहा। डॉक्टरों के मुताबिक, बच्चे को जो तेज बुखार था, उसकी एक वजह शरीर में फंसी जंग लगी सुई भी हो सकती है। सर्जरी के कुछ दिनों बाद उसकी हालत में सुधार हुआ और उसे आईसीयू से बाहर शिफ्ट किया गया।

सरकारी जांच में मां पर आरोप तय : 21 जनवरी को चीन की विभिन्न सरकारी एजेंसियों- पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो, स्वास्थ्य आयोग और महिला महासंघ- की संयुक्त जांच में पुष्टि हुई कि बच्चे को चोटें उसकी मां ने ही दी थीं। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि मां कम शिक्षित है और उसने बिना वैज्ञानिक समझ के यह तरीका अपनाया। उसमें मानसिक तनाव और चिंता के लक्षण भी पाए गए। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस मामले में महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किस स्तर तक पहुंची है।

सोशल मीडिया पर आक्रोश : घटना सामने आते ही चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुस्सा फूट पड़ा। कई यूजर्स ने इसे भयावह और अमानवीय बताया, वहीं कुछ ने मांग की कि बच्चे को उसके माता-पिता से अलग सुरक्षित माहौल में रखा जाए।

शादी करो, ?12.5 लाख पाओ! बच्चा होने पर इनाम होगा डबल, यूएई के अरबपति बॉस का बड़ा ऐलान

अबुधाबी , एजेंसी। यूएई के कॉर्पोरेट जगत से एक ऐसी खबर आई है जो किसी फिल्मी स्टोरी जैसी सुनहरी लगती है, जहां एक कर्मचारी की निजी खुशियों को कंपनी अपनी जिम्मेदारी मानकर जश्न मना रही है। कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपकी शादी के तोहफे के तौर पर कंपनी की तरफ से आपके बैंक खाते में सीधे 12.5 लाख रुपये (50,000 दिरहम) आ जाएं। संयुक्त अरब अमीरात के दिग्गज कारोबारी समूह अल हब्तूर ग्रुप ने अपने अमीराती कर्मचारियों के लिए इस हकीकत को जमीन पर उतार दिया है। इस अनूठी पहल के सूत्रधार हैं अरबपति उद्योगपति खलाफ अल हब्तूर, जिन्होंने समाज की बुनियादी इकाई यानी परिवार को मजबूत करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। उनका विजन सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इसे राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई युवा कर्मचारी शादी के बंधन में बंधता है, तो उसे 50,000 दिरहम का शुरुआती सहयोग दिया जाएगा। उत्साह बढ़ाने वाली बात यह है कि यदि अगले दो वर्षों के भीतर उस कर्मचारी के घर संतान का सुख मिलता है, तो कंपनी की ओर से मिलने वाली यह वित्तीय सहायता दोगुनी होकर सीधा लाभ पहुंचाएगी। खलाफ अल हब्तूर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी इस सोच को दुनिया के सामने रखते हुए कहा कि विवाह और संतानोत्पत्ति केवल किसी व्यक्ति का निजी चुनाव नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ और मजबूत समाज की नींव है। उनका मानना है कि वर्तमान दौर की महंगाई और करियर की भागदौड़ में अक्सर युवा परिवार शुरू करने से कतराते हैं, ऐसे में एक नियोक्ता के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस राह को आसान बनाएं। 1970 में स्थापित अल हब्तूर ग्रुप, जो आज होटल से लेकर रियल एस्टेट तक के बड़े साम्राज्यों का मालिक है, अब अपनी इस मानवीय पहल के जरिए अमीरात के युवाओं को एक सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्थिर भविष्य का भरोसा दे रहा है। यह कदम न केवल कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है, बल्कि अन्य कंपनियों के लिए भी एक मिसाल पेश करता है कि कैसे व्यापारिक लाभ से परे जाकर सामाजिक स्थिरता में निवेश किया जा सकता है।

पनामा नहर पर दबदबे के चीन के मंसूबों को झटका, कंपनी को बंदरगाह संचालन की छूट खतरे में

पनामा सिटी एजेंसी। पनामा के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए एक फैसले से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पनामा नहर पर वर्चस्व कायम करने के चीनी मंसूबों को झटका लगा है। पनामा के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार देर रात अपने एक फैसले में पनामा नहर के दोनों छोरों पर बंदरगाह के संचालन के लिए हांगकांग की कंपनी को दी गई छूट को असांविधानिक बताया। इससे रणनीतिक रूप से अहम जलमार्ग पर चीनी प्रभाव को रोकने की अमेरिकी कोशिश को बल मिलेगा।

चीनी कंपनी ने फैसले पर जताई नाराजगी : पनामा के सुप्रीम कोर्ट के बयान में इस बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया गया है कि अब बंदरगाहों का क्या होगा। सीके हचिसन की सहयोगी चीनी कंपनी पनामा पोर्ट्स कंपनी ने कहा कि उसे अभी तक इस फैसले के बारे में सूचित नहीं किया गया है। हालांकि, उसने जोर देकर कहा कि उसकी रियायत पारदर्शी अंतरराष्ट्रीय बोली का नतीजा थी। कंपनी ने बयान में कहा कि यह फैसला कानून पर आधारित नहीं है। यह न केवल पीपीसी और उसके अनुबंध को खतरे में डालता है बल्कि उन हजारों पनामानियाई परिवारों की भलाई और स्थिरता को भी खतरे में डालता है जो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से बंदरगाह की गतिविधि पर निर्भर हैं। कंपनी ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा, यह फैसला देश में कानून के शासन और कानूनी निश्चितता को भी खतरे में डालता है। कंपनी ने कहा कि वह पनामा या कहीं और कानूनी कार्रवाई करने के सभी अधिकार सुरक्षित रखती है।

ऑडिट के बाद आया फैसला : कोर्ट का यह फैसला पनामा के कंट्रोलर की तरफ से किए गए ऑडिट के बाद आया। इसमें 2021 में दी गई छूट के 25 साल के विस्तार में गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया था। पनामा नहर पर चीन के प्रभाव को रोकना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं में शुमार है। अमेरिकी विदेश मंत्री के तौर पर मार्को रूबियो अपनी पहली यात्रा पर पनामा पहुंचे थे। पनामा सरकार के संचालन में चीन के दखल न होने की बात पर रूबियो ने साफ कर दिया था कि अमेरिका इन बंदरगाहों के संचालन को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला मानता है। पनामा नहर क्यों है अहम, जिस पर कब्जे से घबराया अमेरिका पनामा नहर वैश्विक भू-राजनीति में अहम मानी जाती है। यह 82 किलोमीटर लंबी नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पूरी दुनिया का छह फीसदी समुद्री व्यापार पनामा नहर से ही होता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए भी पनामा नहर बेहद अहम है क्योंकि अभी न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने वाले मालवाहक जहाजों को पनामा नहर के जरिए दूरी 8370 किलोमीटर पड़ती है, लेकिन अगर पनामा नहर की बजाय पुराने मार्ग से माल भेजा जाए तो जहाजों को पूरे दक्षिण अमेरिकी देशों का चक्कर लगाने के बाद सैन फ्रांसिस्को जाना होगा और ये दूरी 22 हजार किलोमीटर से ज्यादा होगी। अमेरिका का 14 फीसदी व्यापार पनामा नहर के जरिए ही होता है। कह सकते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ही पनामा नहर लाइफलाइन का काम करती है। अमेरिका के साथ ही दक्षिण अमेरिकी देशों का बड़ी संख्या में आयात-निर्यात भी पनामा नहर के जरिए ही होता है। एशिया से अगर कैरेबियाई देश माल भेजना हो तो जहाज पनामा नहर से होकर ही गुजरते हैं। खुद पनामा की अर्थव्यवस्था इस नहर पर निर्भर है और पनामा की सरकार को पनामा के प्रबंधन से ही हर साल अरबों डॉलर की कमाई होती है। पनामा नहर पर कब्जा होने की स्थिति में पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंख्ला बाधित होने का खतरा है। पनामा नहर का निर्माण साल 1881 में फ्रांस ने शुरू किया था, लेकिन इसे साल 1914 में अमेरिका द्वारा इस नहर के निर्माण को पूरा किया गया। इसके बाद पनामा नहर पर अमेरिका का ही नियंत्रण रहा, लेकिन साल 1999 में अमेरिका ने पनामा नहर का नियंत्रण पनामा की सरकार को सौंप दिया। अब इसका प्रबंधन पनामा कैनाल अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। पनामा नहर को इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है और इसे आधुनिक दुनिया के इंजीनियरिंग के सात अजूबों में से एक माना जाता है। पनामा नहर को लेकर पर्दे के पीछे चीन और अमेरिका के बीच तनातनी चल रही है। इसे लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ रहा है। चीन अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत के जरिए पूरी दुनिया के जलमार्गों पर अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग, पुलिस बल तैनात

मुंबई (एजेंसी)। बालीवुड फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई। घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीमें वहां पहुंचीं। रोहित शेट्टी मुंबई के जुहू इलाके में रहते हैं। उनके घर के पास बॉलीवुड की कई हस्तियों के घर भी हैं। मुंबई पुलिस ने बताया कि ये घटना शनिवार रात करीब 3 बजे हुई। अज्ञात हमलावरों ने चार राउंड फायरिंग की। इसके बाद जुहू में रोहित शेट्टी के घर के आसपास सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने हर एंगल से जांच कर रही है। हमले की वजह अभी पता नहीं चली है। मामले में अभी तक किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है।

लावारिस ट्रॉली बैग देख मची सनसनी, खोला तो निकला युवती का शव, जांच शुरु

रोहतास (एजेंसी)। रोहतास में ट्रॉली बैग में शव मिलने से सनसनी फैल गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और छानबीन शुरू की। मौके पर एफएसएल की टीम भी बुलाई गई। मामला डेहरी थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित सब्जी मंडी के पीछे का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जब बैग को खोलकर देखा गया तो उसमें अंदर युवती की डेडबॉडी निकली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। युवती की हत्या क्यों और किसने की? इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में रोहतास जिले के साइबर डीएसपी ने बताया कि रविवार सुबह से सूचना मिली कि डेहरी नगर थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी में एक सूटकेस में पड़ा हुआ है, जिसके बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची और बैग को खोला। इस दौरान बैग के अंदर एक युवती का शव मिला। हालांकि युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और युवती की पहचान के लिए लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।

कोलकाता के रेस्टोरेंट में यूट्यूबर सायक को मटन की जगह बीफ परोसा, वीडियो वायरल

बीजेपी बोली-बांग्लादेश की तरह पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं को जबरन खिलाया जा रहा गोमांस

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक रेस्टोरेंट में मटन की जगह बीफ परोसने का मामला सामने आया। बंगाली यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर सायक चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मटन स्टेक ऑर्डर किया था, लेकिन उन्हें बीफ स्टेक परोस गया। उन्होंने बीफ को मटन समझकर खा लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सायक चक्रवर्ती शुक्रवार रात अपने दोस्तों के साथ पार्क स्ट्रीट स्थित एक पब-रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे। उन्होंने एक मटन स्टेक ऑर्डर किया था। कुछ देर बाद वेटर एक और प्लेट लेकर आया और कहा कि यह मटन स्टेक है। तब सायक को शक हुआ कि पहले परोसा गया स्टेक मटन नहीं था। सायक ने जब वेटर से सवाल किया तो उसने दावा किया कि दो स्टेक ऑर्डर किए गए थे। एक मटन और एक बीफ। सायक का कहना है कि उन्होंने सिर्फ एक मटन स्टेक ऑर्डर किया था। वीडियो में सायक वेटर से बहस करते और जवाब मांगते दिख रहे हैं। रेस्टोरेंट मैनेजर और वेटर वीडियो में माफी मांगते नजर आते हैं। वीडियो में सायक यह कहते भी सुने गए कि वह ब्राह्मण हैं। इस घटना से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसके बाद पार्क स्ट्रीट पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। वेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी आईटी हेड अमित मालवीय ने एक्स पर सायक का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि बांग्लादेश की तरह पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं को जबरन गोमांस खिलाया जा रहा है। आज जो हम देख रहे हैं, वह कोई छिटपुट घटना नहीं है, बल्कि चेतावनी है। अगर टीएमसी सत्ता में वापस आती हैं, तो यह अपवाद नहीं रहेगा, बल्कि आम बात हो जाएगी। यह पसंद या खानपान की आदतों का मामला नहीं है, बल्कि हिंदुओं की आस्था और विश्वासों को पूरी तरह से कुचलने का मामला है। ममता प्रशासन गायों की तस्करी और अवैध हत्या पर लगाम लगाने में विफल रहा है।

अल्मोड़ा में हादसा- दिल्ली के बुजुर्ग दंपति की मौत, खाई में गिरकर दूसरी सड़क पर पलटी कार

अल्मोड़ा (एजेंसी)। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक हृदयविदारक सड़क दुर्घटना सामने आई है, जहां बाड़ेछीना-सेराघाट मोटर मार्ग पर दिल्ली से घूमने आए एक परिवार की कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस भयावह हादसे में कार सवार बुजुर्ग दंपति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार पहाड़ी से लुढ़कते हुए लगभग 60 मीटर नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार पूरी तरह पिचक गई और दंपति के शव वाहन के मलबे में ही फंस गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली के महरौली (मंगलपुरी) निवासी 75 वर्षीय प्रणब राय, अपनी 72 वर्षीय पत्नी शुभी राय और 52 वर्षीय बेटे सिद्धार्थ राय के साथ देवभूमि की यात्रा पर थे। शनिवार की सुबह उन्होंने नैनीताल के प्रसिद्ध कैंची धाम में दर्शन किए थे और वहां से लगभग 250 किलोमीटर दूर मुनस्यारी में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए निकले थे। दोपहर करीब तीन बजे, बाड़ेछीना-सेराघाट मार्ग पर कसान बैंड के पास उनकी स्कॉर्पियो कार अचानक बेकाबू हो गई और सुरक्षा बैरियर को तोड़ते हुए खाई में समा गई। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और धौलछीना थाना पुलिस तुरंत रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंचे। कार ऊंचाई से गिरने के बाद सड़क पर उल्टी होकर गिरी थी, जिस कारण उसकी छत बुरी तरह पिचक गई थी। कार चला रहे सिद्धार्थ राय को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, जिनकी सांसें चल रही थीं। मौके पर मौजूद शिक्षक राकेश मेहरा ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए बिना समय गंवाए घायल सिद्धार्थ को अपने निजी वाहन से तुरंत धौलछीना अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। सिद्धार्थ पेशे से आर्किटेक्ट हैं और उनकी पत्नी गंभीर बीमारी के चलते इस यात्रा पर साथ नहीं आई थीं।

एसआईआर से व्यापक जन-पीड़ा हुई और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास कम हुआ

-सीएम ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर जताई आपत्ति, लगाए आरोप

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर एसआईआर पर गंभीर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से व्यापक जन-पीड़ा हुई है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास कम हो गया है। एक पोस्ट साझा करते हुए ममता बनर्जी ने चिंता व्यक्त की और चेतावनी दी है कि इस प्रक्रिया से जनता को व्यापक कष्ट हो रहा है। उन्होंने करीब 8,100 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की तैनाती पर कड़ी आपत्ति जताई है और बताया है कि उनकी भूमिकाएं, शक्तियां और अधिकार मौजूदा चुनाव कानूनों में निहित नहीं हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यह भी बताया है कि कुछ पर्यवेक्षक गैरकानूनी रूप से पोर्टल तक पहुंच बना रहे हैं और उसे नियंत्रित कर रहे हैं, जिससे वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के तरीके से डेटा में हेरफेर किया जा रहा है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से इस संस्थागत अतिक्रमण को रोकने, संवैधानिक निकायों में जनता का विश्वास बहाल करने और नागरिकों की गरिमा, अधिकारों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।

एक पत्र में सीएम ममता ने चेतावनी दी कि जिस तरह से एसआईआर का संचालन किया जा रहा है, उससे लोगों को अत्यधिक असुविधा और पीड़ा हुई। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप करीब 140 मौतें हुई हैं और इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए अंजाम दिया गया है। सीएम ममता ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगभग 8,100 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की तैनाती पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे भारत के चुनावी इतिहास में अभूतपूर्व बताया। उन्होंने कहा कि इन सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण या सिद्ध विशेषज्ञता के बिना चुनाव आयोग द्वारा एकतरफा रूप से नियुक्त किया जा रहा है जिसे उन्होंने विशेषज्ञ, संवेदनशील और अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया बताया।

पहले नफरत भरा भाषण, धमकियां और अब सीएम ममता पर लगा रहे आरोप

-बीजेपी नेता मालवीय ने हुमायूं कबीर के आरोपों की कड़ी आलोचना की

कोलकाता (एजेंसी)। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जन उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर के उन आरोपों की कड़ी आलोचना की है, जिनमें उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी ने उन्हें 2024 में नफरत फैलाने वाला भाषण देने के लिए उकसाया था। मालवीय ने नफरत फैलाने वाले भाषण से धमकियों और फिर राजनीतिक प्रोत्साहन के दावे तक के इस बदलाव की निंदा की। उन्होंने कहा कि यही वह हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने 2024 में हिंदुओं को भागीरथी नदी में फेंकने की धमकी दी थी। नफरत फैलाने वाला भाषण। धमकियां और अब यह दावा कि इसे राजनीतिक प्रोत्साहन दिया गया था। इससे पहले एक कार्यक्रम में कबीर ने 2024 में हिंदुओं के खिलाफ की गई अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी के प्रचार के दौरान टीएमसी सांसद की जीत तय करने के लिए सीएम ममता बनर्जी के निर्देश पर उन्हें यह भाषण देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी हिंदुओं से नफरत नहीं की और न ही वे जानबूझकर ऐसा कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे खेद है। सीएम ममता बनर्जी के शब्दों को ध्यान में रखते हुए, मैंने अपने हिंदू भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। मैं अपने उस बयान के लिए तहे दिल से माफी मांगता हूं।

जेलों में बंद सात कैदियो को पाकिस्तान ने किया रिहा, अटारी-वाघा बॉर्डर से भारत पहुंचे

-रिहा शख्स बोला-पाक जेलों में बंद भारतीयों की हालत है खराब, उन्हें भी कराएं आजाद

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान ने जेलों में बंद सात कैदियों को रविवार को भारत को सौंप दिया। भारतीय कैदियों की वापसी अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते से हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सीमा पर तैनात अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान ने सात कैदियों की रिहाई का आदेश दिया था, जिनको पाकिस्तानी रेंजर्स ने 7 कैदियों को भारतीय सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए सात कैदियों को भारत की तरफ आते ही सबसे पहले आब्रजन कार्यालय तक लाया गया। इन सातों में से 6 पंजाब के रहने वाले हैं, जिनमें से 4 फिरोजपुर, एक लुधियाना और एक जालंधर का रहने वाला है। वहीं, बचा एक कैदी उत्तर-प्रदेश का है। सभी साल 2023 में पाकिस्तान चले गए थे। ये तब हुआ, जब तीन साल पहले पंजाब में बाढ़ आई थी और ये साल लोग अपने जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान की कैद से छूटकर भारत आने वाले एक शख्स ने बताया कि जब उसके गांव में पानी का तेज बहाव आया तो पुल गिर गया। उस समय पानी का बहाव बहुत तेज था और वह बहकर पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान के अधिकारियों को उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और जेल भेज दिया। शख्स ने बताया कि उसे तीन महीनों तक पाकिस्तान की जेल में रहना पड़ा, जहां बेरहमी से पीटा गया। पाकिस्तान की जेलों में कैद भारतीयो की हालत बेहद खराब है। कोई अंधा है तो किसी के पैर खराब हैं।

अच्छा बजट वह है जो गरीब के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशहाली लाए

सपा प्रमुख ने अखिलेश ने आम बजट पर कसा तंज-सरकार से कोई उम्मीद नहीं

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट 2026 के पेश होने से पहले ही हमला बोला। उन्होंने आम बजट को लेकर कहा कि इससे हमें कोई उम्मीद है। उन्होंने सरकार से ही ना उम्मीद होने की बात कही। दरअसल, 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आम बजट को अहम माना जा रहा है। ऐसे में अखिलेश इसकी पहले से ही मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। दरअसल आम बजट 2026 रविवार सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं। इससे पहले संसद भवन परिसर में आयोजिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी।

आम बजट 2026 पेश होने से पहले अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, उसके बजट से क्या उम्मीद करें? ये बजट पांच फीसदी लोगों के लिए बनता है। सरकार ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए थे, क्या उसपर खरी उतरी है? अखिलेश ने कहा पिछले तमाम बजटों में देखने को मिला है कि यह एक बटा 20 लोगों के लिए बनता है यानी 5 फीसदी लोगों के लिए ही बजट बनाया जाता है। उनहोंने आगे कहा कि आज सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि उन्होंने जो वादे किए थे, क्या वे पूरे हुए? पीछे मुड़कर वे देखें और सोचें कि क्या उन वादों पर खड़े उतरे हैं? स्मार्ट सिटी बनाने के बहाने पैसा बहाया गया। उन्होंने कहा कि अच्छा बजट वह है जो गरीब के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशहाली ले आए। सरकार इसमें विफल रही है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा कि जिस इंदौर शहर को सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले थे। सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर चर्चा हो रही थी। वहां लोगों की कैसे जान चली गई? उन्होंने कहा कि जो सरकार गरीबों की प्रति व्यक्ति आय ना बता पा रही हो। ये कह रहे हैं कि हमने इतने गरीब लोगों को पीडीएस सिस्टम और खाना देने से जोड़ दिया है, उस पर क्या टिप्पणी की जाए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि इस बजट से रिफॉर्म नहीं, डिफॉर्म होगा।

उन्होंने सवाल किया कि किसानों की आय दोगुनी करने के दावों का क्या हुआ। उन्होंने प्रभु श्रीराम का जिक्र भी इस मौके पर किया। उन्होंने कहा कि टीवी वाले राम जी यानी मेरठ सांसद अरुण गोविल को पीछे की पंक्ति में बैठाए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये कैसे रामभक्त हैं। अगर वह टीवी वाले राम जी को प्रधानमंत्री के बगल में बैठाएं तब माना जाए। दरअसल, अखिलेश अपने बगल में अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद को बैठाते दिखे। इसके जरिए वे एक बड़ी राजनीति करते दिख रहे हैं।

वहीं, सपा सांसद प्रो. रामगोपाल यादव ने भी कहा कि इस बजट से हमें कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि तीन-चार व्यापारी जो बता देंगे, वैसा बजट बनकर आ जाएगा। आम जनता के लिए इससे कोई उम्मीद नहीं है। अखिलेश यादव ने बयान से विपक्ष का बजट पर रुख साफ कर दिया है। इस बजट का विपक्ष हर हाल में विरोध करेगा। यह तय माना जा रहा है। वहीं, सत्ताधारी पक्ष की ओर से बजट में गरीब और किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ नई योजनाओं का ऐलान भी हो सकता है। ऐसे में निर्मला सीतारमण के नौवें बजट पर हर किसी की नजर है।

हजार गौरव गोगोई और राहुल गांधी भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे: सीएम सरमा

कांग्रेस को सिर्फ अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की चिंता है, न कि मूल निवासियों की

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि कांग्रेस को सिर्फ अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की चिंता है, न कि असम के मूल निवासियों के हितों की। उन्होंने गुवाहाटी में कहा कि हजार गौरव गोगोई और राहुल गांधी भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी असम के लोगों के लिए स्थिति बहुत नाजुक है, और यह राज्य में उनके अस्तित्व का सवाल है। मिया मुसलमान विवाद पर उन्होंने कहा कि मिया मुसलमान शब्द मैंने नहीं गढ़ा है और यह शब्द खुद वह समुदाय इस्तेमाल करता है जो बांग्लादेश से आकर बस गए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस शब्द को इस्तेमाल किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक्स पर पोस्ट में सरमा ने लिखा- ये कोर्ट के अपने शब्द हैं। असम पर चुपचाप और धोखे से हो रहा जनसांख्यिकीय हमला निचले असम के भू-रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिलों के नुकसान का कारण बन सकता है। अवैध प्रवासियों की संख्या इन जिलों को मुस्लिम-बहुल क्षेत्र में बदल रही है। इसके बाद यह सिर्फ समय की बात होगी जब बांग्लादेश के साथ उनके विलय की मांग की जा सकती है। निचले असम के नुकसान से उत्तर पूर्व का पूरा भूभाग बाकी भारत से अलग हो जाएगा और उस क्षेत्र के समृद्ध प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र के हाथ से निकल जाएंगे। सरमा ने कहा कि ऐसी चिंताओं को स्वीकार करना सांप्रदायिकता या नफरत नहीं है। सीएम सरमा के बयान पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हिमंत सरमा अपने बयानों को सही ठहरने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एक कार्यकारी रिपोर्ट की भाषा को सुप्रीम कोर्ट से जोड़ना कोर्ट की अवमानना है। सीएम सरमा ने 27 जनवरी को कहा था कि राज्य में एसआईआर में 4 से 5 लाख मिया मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि सरमा और बीजेपी सीधे तौर पर मिया समुदाय के खिलाफ हैं। उन्होंने लोगों से मिया समुदाय को परेशान करने की अपील की। उनका कहना था कि जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी, वे असम छोड़कर नहीं जाएंगे। मिया बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अपमानजनक शब्द है। असम सीएम के मुताबिक वे मूल निवासियों के संसाधनों, नौकरियों और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कई ढांचागत समस्याएं हैं जिनका समाधान एक दशक से नहीं हुआ

-केंद्रीय बजट 2026 पर विपक्ष ने उठाए सवाल, निजी पूंजी निवेश में खास वृद्धि नहीं हुई

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार को बजट सत्र में भाग लेने संसद पहुंचीं और कहा कि उन्हें ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। इसके अलावा, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कई ढांचागत समस्याएं हैं जिनका समाधान एक दशक से नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कई ढांचागत समस्याएं हैं जिनका समाधान एक दशक से नहीं हुआ है। निजी पूंजी निवेश में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। विदेशी निवेश में गिरावट आई है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद ढांचागत असमानताओं को समझेंगे और ईमानदारी से उनका समाधान करेंगी।

आईयूएमएल सांसद ई टी मोहम्मद बशीर ने कहा कि एमजीएनआरईजीए की दुर्दशा तो सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक नाजुक मोड़ है। कई मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, खासकर भारत की मौजूदा स्थिति में। कई चीजों को गंभीरता से निपटाने की जरुरत है। हमें उम्मीद है कि ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम सभी एमजीएनआरईजीए की दुर्दशा जानते हैं...उन्होंने इसकी पूरी संरचना बदल दी है। यह मनमोहन सिंह की तत्कालीन सरकार द्वारा उठाया गया सबसे क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने इसे बर्बाद कर दिया है।

बशीर ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार कदम उठाएगी, अगर गांवों पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए इस लिहाज से भी मुझे उम्मीद है कि सरकार न्याय करेगी। इतना ही नहीं, वित्तीय क्षेत्र में भी कई संकट हैं। उनका भी समाधान होगा। केरल के संबंध में हम न्याय चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि वे केरल के लिए भी एम्स और ऐसे ही राष्ट्रीय संस्थानों का उपयोग करेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में बैठक के बाद केंद्रीय बजट 2026-27 को मंजूरी दे दी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही-चीनी भेंट की।

यूजीसी नियम बने बीजेपी के लिए गले की फांस, यूपी में हो सकता है नुकसान

-सवर्ण जाति के संगठनों और छात्रों में नाराजगी बरकरार, फिलहाल कोर्ट ने लगा दी है रोक

नई दिल्ली (एजेंसी)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल रोक लगाए जाने के बाद भले ही सरकार को राहत मिली हो, लेकिन इससे बीजेपी की राजनीतिक मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। खासकर सवर्ण जातियों के संगठनों और छात्रों में नाराजगी बरकरार है। उनका कहना है कि जब तक यूजीसी के नियम पूरी तरह वापस नहीं लिए जाते, तब तक इसका विरोध करते रहेंगे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूजीसी का यह विवाद अब बीजेपी के लिए 'गले की फांस' बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद करणी सेना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा, परशुराम सेना समेत कई सवर्ण संगठन सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। इससे संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। इस विरोध का सबसे बड़ा केंद्र यूपी है। यूपी में बीजेपी के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर असंतोष खुलकर सामने आया है।

कई स्थानीय और जिला स्तर के नेताओं ने पद से इस्तीफा तक दे दिया है। पार्टी के कुछ सवर्ण नेताओं का कहना है कि नए नियमों को लेकर समर्थकों को समझाना मुश्किल हो रहा है। एक विधायक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि परंपरागत सवर्ण वोटरों की अनदेखी से समाज में बेचैनी बढ़ी है और यूजीसी विवाद ने इसे और गहरा कर दिया है। बीजेपी के सामने दुविधा यह है कि यदि वह यूजीसी के नियमों का खुलकर समर्थन करती है तो सवर्णों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, और यदि नियमों को वापस लेती है तो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विरोध का खतरा है। ऐसे में पार्टी के लिए सामाजिक संतुलन बनाए रखना चुनौती बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दृष्टि से यूपी में यह मुद्दा और भी संवेदनशील है। प्रदेश की आबादी में ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य समेत सवर्ण जातियां करीब 22 फीसदी हैं, जिन्हें बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। जनरल कैटेगरी के युवाओं का आरोप है कि नए नियम 'रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन' को बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह असंतोष बना रहा तो 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है।

दूसरी ओर विपक्ष ने इस मुद्दे पर सधे हुए बयान देकर सवर्ण वोटरों को साधने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सरकार पर बिना पर्याप्त चर्चा के नियम लागू करने का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर, यूजीसी नियमों का विवाद अब केवल कानूनी नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए सियासी परीक्षा बन चुका है।